आप पार्टी सरकार के

3 साल! दिल्ली बेहाल!

बर्बाद गुलिस्तां करने को.. बस एक ही उल्लू काफी है..
हर शाख पे उल्लू बैठा है.. अंजामें गुलिस्तां क्या होगा .?

दिल्ली सरकार

#AapFailedDelhi

हवाला मंत्री

फर्जी डिग्री मंत्री

सैक्स सी.डी. मंत्री

बिल्डर माफिया मंत्री

'जनलोकपाल' नहीं 'जोकपाल' - **98** हजार बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा - एक साल में रिकार्ड **9149** लोगों की सांस से जुड़ी बिमारी से मौत - एक साल में रिकार्ड **1** लाख **40** हजार लोगों की **cholera** ओर डायरिया जैसी बिमारियों से मौत - **111** डिस्पेंसरियां बन्द - खराब सेवा के कारण **1** साल में डी.टी.सी. से **54** करोड़ यात्रियों की कमी - **1272** बसें डी.टी.सी. से गायब - पहली बार दिल्ली मैट्रो का काम दो साल लेट - **1** साल में दो बार मैट्रो का किराया बढ़ाया गया - **2** लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन अटकी - ओर तो ओर इनके राज में.. **2** साल में **3** बार पानी ओर सीवर के चार्ज में बढ़ोतरी की गई !

विकास

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी

क्रम संख्या	विषय सूची	पेज नः
1	# आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर फेल	1–4
2	# आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में चरमराई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था	5–10
3	#आप पार्टी ने बिगाड़ी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था	11–19
4	#आम आदमी पार्टी शिक्षा के मामले में फेल	20–25
5	#शहरी गरीबों को लेकर आम आदमी पार्टी की असफलता	26–30
6	#महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की विफलताएं	31–33
7	#पर्यावरण के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विफलाएं	34–36
8	# मुफ्त पानी की सप्लाई का झूठ	37–38

#आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर फेल

सत्ता हथियाने के लिए आप पार्टी के दिखावे के सिद्धांत

अरविंद केजरीवाल सरकार की तीन साल की कहानी उस व्यापारी के सपने के समान है जिसको लोगों ने 67 सीटे थमा डाली परंतु उसने बार–बार दिल्ली के आम आदमी को गुमराह किया है। उन्होंने मीडिया स्टंट तथा मुसीबतें बनाकर सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाया है। राष्ट्रीय राजधानी एक ऐसी दिशाहीन सरकार द्वारा चलाई जा रही है और दिल्ली के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और अब वे ड्रामा पोलिटिक्स बनाम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास की तुलना कर सकती है।

केजरीवाल सरकार के पिछले तीन साल दिल्ली के लिए न सिर्फ व्यर्थपूर्ण रहे है बल्कि उन्होंने उन मुख्य बातों जिस पर आम आदमी पार्टी बनी थी चुनकर आई थी। उनपर भी उन्होंने एक के बाद एक समझौते किए है। टीम केजरीवाल ने बड़े सहज तरीके से लोकपाल के सिद्धांतो, पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र को दरकिनार करके वीआईपी संस्कृति, परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

आम आदमी से खास आदमी – वीआईपी संस्कृति

- सत्ता में आने के 49 दिन में केजरीवाल सरकार ने तालकटोरा मे होने वाले सार्वजनिक समारोह में वीआईपी तथा वीवीआईपी एन्ट्री तथा मंत्रियों व विधायकों के लिए पार्किंग की सुविधा की मांग कर डाली।
- **वीवीआईपी मंत्रीमंडल**
  चुनाव से पहले नाटकबाजी करते हुए श्री केजरीवाल ने शपथ पत्र बांटे जिसमें उन्होंने शपथ ली थी कि यदि चुनकर आए तो
  ''मैं लालबत्ती वाली गाड़ी नही लूंगा'',
  ''मैं बड़ा बंगला नही लूंगा'',
  ''मैं सुरक्षा नही लूंगा''
- परंतु उपर लिखी बातों के उलट आज की सच्चाई यह है कि केजरीवाल जेड प्लस सुरक्षा कवर के साथ चार कारों जिनमें सुरक्षाकर्मी होते है उनके साथ चलते है। मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार को 2 आरामदायक सरकारी बंगले फ्लेगस्टाफ रोड़ पर उनके रहने के लिए दे डाले।

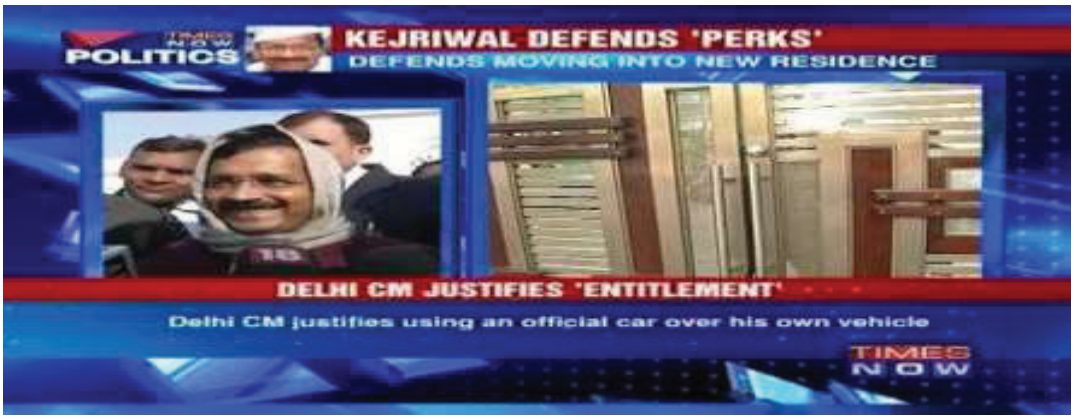

- मुख्यमंत्री की दादागिरी का उदाहरण उस समय मिला जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक जवान महिला ने मुख्यमंत्री पर स्याही फैक दी। उस समय उनकी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा न देने के लिए लताड़ा था।
- इसी प्रकार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया वर्तमान में उस बंगले में रहते है जहां श्रीमती शीला दीक्षित बतौर मुख्यमंत्री रहा करती थी। वे सार्वजनिक परिवहन की जगह एसयूवी ग्रांड विटारा जो एक लग्जरी गाड़ी है उसका इस्तेमाल करते है।
- इसके पश्चात आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार के अन्तर्गत 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर वीआईपी बना डाला ताकि उनके विधायक पार्टी छोड़कर इधर–उधर न जाए। 12 मई 2015 को स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेन्द्र जैन ने अस्पतालों को उनके विधायकों जो रोगी कल्याण समिति के सदस्य है उनको विशेष कमरे देने के लिए कहा। यह आदेश उस समय आया जिस समय दिल्ली के अस्पतालों में नए बेड लगाने के लिए जगह की कमी है।

  (केजरीवाल के 7 जून 2013 के शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिसमें वीआईपी संस्कृति के खिलाफ बड़े–बड़े वायदे किए गए थे। यह सिर्फ वोट बटौरने के लिए किया गया था)

लोकपाल तथा आंतरिक लोकतंत्र

वह पार्टी जो लोकपाल आंदोलन के द्वारा बनाई गई थी उसने बड़े शर्मनाक तरीके से अपने आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को 29 मार्च अर्थात सता में आने के 45 दिन के अंदर ही हटा डाला। जनलोकपाल जिस मुद्दे पर उन्होंने अपने 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया था उनके पास अभी तक कोई लोकपाल नही है और लोकपाल बिल जो केजरीवाल सरकार ने पास किया था उसकी सच्चाई इस प्रकार है।

लोकपाल से जोकपाल की यात्रा

लोकपाल कानून जो कि दिल्ली विधानसभा ने पास किया था उसमें बहुत सारी कमियां है और उसमें कहा गया है कि लोकपाल आफिस में आए किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार सत्ताधारी पार्टी को होगा तथा उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को लोकपाल को विधानसभा में एक मोशन के द्वारा हटाने की विशेष शक्तियां भी दे डाली। क्या कोई भी संस्था इन परिस्थितियों में बिना भय और निष्पक्ष रुप में चल सकती है। लोकपाल की अवधारणा को केजरीवाल ने लोलपाल में बदल दिया। शायद दागी मंत्रियों और विधायकों के विश्वास के पीछे यही कारण है।

इसमें कोई शक नही है कि प्रशांत भूषण व योगेन्द्र यादव को इन गलत चीजों पर उंगली उठाने के कारण निकाला गया है।

यद्यपि यह पार्टी का आंतरिक मामला है परंतु अलोकतांत्रिक तरीके से संस्थापक सदस्यों प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, प्रो0 अनन्त कुमार को निकालने से पार्टी में चल रहे आंतरिक लोकतंत्र के पांखड का भंडाफोड़ होता है। इन सबके पीछे केजरीवाल की राजनीतिक महत्वकांक्षाएं है।

भ्रष्टाचार

चुनाव के प्रचार में भ्रष्टाचार को लेकर किए गए बड़े–बड़े आरोपों के बाद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद बड़ी आसानी से नकली डिग्री रखने वाले श्री जितेन्द्र सिंह तौमर को अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचारित की गई हैल्पलाईन भी गायब हो गई जब केजरीवाल के अपने साथियों के खिलाफ मुकद्में दर्ज होने थे। दूसरे विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने झूठी डिग्री रखने के मामले में खींचा। केजरीवाल जो बिना कोर्ट का फैसला आए बड़े–बड़े आरोप लगाते थे उन्होंने बड़ी सुविधा पूर्वक अपने लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही यह कहकर नही की कि उनके मुकद्में कोर्ट में लंबित है।

लोकपाल का पद खाली है। नए लोकपाल की नियुक्ति इस डर में नही हो रही कि उनके कानून मंत्री और विधायकों की फर्जी डिग्री के खिलाफ मुकद्में हो जाऐंगे।

लोगों/मीडिया को इस्तेमाल करो और अपनी सहूलियत के हिसाब से फैक दो।

अरविन्द केजरीवाल अन्ना हजारे की प्रसद्धि और उनकी ख्याति के बलबूते सत्ता में आए। उन्होंने अपने मार्गदर्शक अन्ना हजारे की इच्छा के खिलाफ चलकर राजनीतिक पार्टी बनाई और प्रसिद्ध प्राप्त करने के बाद अन्ना हजारे को त्याग दिया। उनकी पार्टी को शुरुआत में प्रशांत भूषण ने पैसा दिया और प्रो0 योगेन्द्र यादव तथा प्रो0 आनन्द कुमार जैसे बुद्धिजीवियों के कारण प्रसिद्धी पाई। जब उन्होंने केजरीवाल की महत्वकांक्षा तथा तानाशाह वाली कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेधा पाटकर जैसी सम्मानित समाज सेवी ने भी अपने आप पार्टी छोड़ दी। पार्टी के कई संस्थापक सदस्यों तथा हजारों कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर या तो पार्टी छोड़ दी या उनकों बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि इन लोगों ने अपनी मेहनत और पैसे से पार्टी को खड़ा किया था। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने 2 वर्ष के समय में इतनी विवादपूर्ण नही रही जिसमें संस्थापक सदस्य तथा इमानदार पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया।

आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वह मीडिया के द्वारा उपजी है। श्री केजरीवाल और उसकी टीम ने हमेशा तथ्यों को बिना जांचे विपक्ष पर निशाना साधा है। सत्ता में आने से पहले वे हमेशा मीडिया से अपील करते थे जबकि सत्ता में आने के बाद जब मीडिया ने केजरीवाल सरकार को चुनावी वायदे पूरे न करने पर उजागर करना शुरु किया तब केजरीवाल ने 6 मई 2015 को एक सरकारी आदेश निकाला कि यदि उनकी सरकार की कोई आलोचना करता है तो वह एक अपराधिक मामला आई.पी.सी. के अन्तर्गत मानहानि में कवर होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मई 2015 को ये सारे गैर कानूनी आदेशों पर स्टे लगा दिया। जब कभी भी मीडिया उनके गलत कामों की आलोचना करता है उस समय केजरीवाल सरकार या तो उनकी सचिवालय में एन्ट्री बंद कर देते है या उनको 'बिकाउ' या 'सुपारी जरनालिस्म' कहकर पुकारते है।

यदि आप, AAP कार्यकर्ता नही है तो आपके लिए कोई स्थान नही है।

दिल्ली सरकार ने 16 अप्रेल 2015 को कुछ रिक्त स्थानों के लिए विज्ञापन दिया और आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2015 रखी। यह इसलिए किया गया था ताकि वे दिल्ली सरकार में कुछ पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को रख सके।

केजरीवाल ने अपने पहले 100 दिनों में बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार और पांखडी सरकार दिल्ली को दी।

राज्यसभा नामांकन

अरविन्द केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सबसे अलग हटकर पार्टी होगी और उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया जब जीएसटी के समर्थन चार्टड एकाउंटेन्ट श्री एन.डी. गुप्ता जो कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के चहेते है उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया। इसी प्रकार श्री सुशील गुप्ता जो कि "mass-based की जगह maal-based" नेता है उनको भी राज्यसभा में भेज दिया।

#आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में चरमराई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

डीटीसी के बेड़े का बुरा हाल

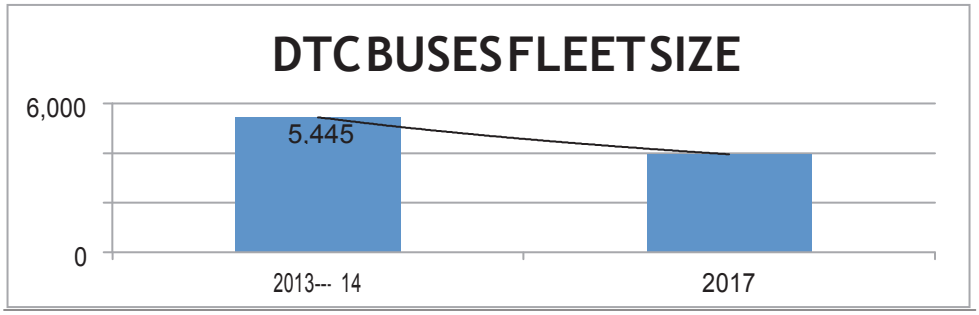

- **डीटीसी बेड़े का आकार :** आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में डीटीसी के बेड़े से 1273 बसे हटा दी गई। 2013–14 यानि कांग्रेस कार्यकाल में डीटीसी के बेड़े में 5223 बसें थी जो कि अगस्त 2017 में कम होकर 3,951 रह गई।
- **डीटीसी बेड़े का उपयोग :** डीटीसी के बेड़े के इस्तेमाल में कमी आई है, जहां 2013–14 में यह इस्तेमाल 85.51 प्रतिशत था वह 2015–16 में घटर 83.63 प्रतिशत रह गया। जिस शहर में पहले से ही डीटीसी बस के बेड़े का आकार कम हो रहा है उसमें डीटीसी के बेड़े के उपयोग में कमी सरकार की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।
- **डीटीसी बेड़े में शामिल नई बसें :** कांग्रेस के आखिरी 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली में डीटीसी की 3,125 बसें जोड़ी गई थी। जबकि केजरीवाल सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में केवल 2 बसे डीटीसी के बेड़े में जोड़ी है।
- **दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रां में बसों की कमी :** दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली लो–फ्लोर बसें केवल 163 रह गई है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में बसों की सेवाएं काफी प्रभावित हुई है। डीटीसी ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में और बसें जोड़ने पर असमर्थता जाहिर की है क्योंकि स्टेन्डर्ड फ्लोर बसों की संख्यां में कमी आ रही है।
- **2025 में कोई बस सेवा नही होगीः** एसटीए बोर्ड ने केजरीवाल सरकार को 16.3.2017 को यह सूचना दी थी कि यदि बसों के बेड़े में इसी प्रकार कमी होती रही तो 2025 में कोई बस नही बचेगी।
- वर्तमान की बसों के बेड़े में बहुत सारी ऐसी बसें है जो 12 साल पूरा होने से पहले ही 7.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है।
- **बसों की खराबी :** डीटीसी की 1000 बसों में खराबी की घटनाएं जो कि 2013–14 में 3.95 थी वह 2015–16 में 4.5 प्रतिशत हो गई।

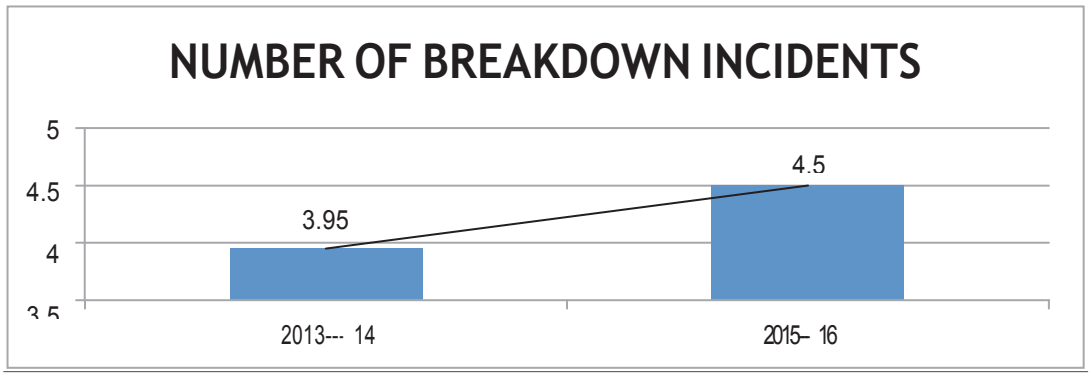

डीटीसी के यात्रियों में होती कमी।

- **डीटीसी के यात्रियों में कुल कमी :** जैसे ही डीटीसी बेड़े में बसों की संख्या कम होती है उसके कारण यह प्रणाली अविश्वसनीय हो जाती है तथा लोगों का विश्वास इस प्रणाली से उठने लगता है। कांग्रेस के कार्यकाल 2013–14 में जहां डीटीसी के द्वारा 43 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे वह आप पार्टी के कार्यकाल नवम्बर 2016 में कम होकर 30 लाख हो गए। इस प्रकार यह साफ जाहिर होता है कि डीटीसी से यात्रा करने वाले प्रतिदिन 13 यात्रियों में कमी आई है, जो कि अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। यदि हम आप पार्टी के 3 वर्षो की गणना करे तो जबसे यह सरकार आई है तब से डीटीसी से चलने वाले 142 करोड़ यात्रियों में कमी है।
  142 करोड़ डीटीसी के यात्रियों की कमी न सिर्फ वित्तिय घाटे को दर्शाता है बल्कि इस कमी के कारण लोगों ने अपने व्यक्तिगत वाहन चलाने शुरु कर दिए जिसके कारण प्रदूषण में बेहताशा वृद्धि हुई।
- **डीटीसी के द्वारा प्रति बस यात्रा करने वाले यात्रियों में कमी :** कांग्रेस के कार्यकाल 2013–14 में जहां प्रति बस से प्रतिदिन 952 यात्री यात्रा करते थे वह आम आदमी पार्टी के कार्यकाल 2015–16 में 927 रह गए।
- **डीटीसी से चलने वाले यात्रियों प्रति वर्ष की कमी :** कांग्रेस के कार्यकाल 2013–14 में जहां प्रति वर्ष डीटीसी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 159 करोड़ थी जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल 2015–16 में 129 करोड़ रह गई। 2013 से औसतन 8.88 प्रतिशत वार्षिक कमी आ रही और कुल मिलाकर यह कमी 34 प्रतिशत हो गई है। (नवम्बर 2016 के उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार)

मेट्रो किराए में बढ़ौतरी : सरकार का इनएफीसेंसी टैक्स

- **मेट्रो किराए में बढ़ौतरी :** केजरीवाल सरकार ने लास्ट माईल कनैक्टीविटी को बढ़ाने की बजाए एक साल में दो बार मेट्रो के किराए बढ़ा दिए तथा कम से कम 8 से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 60 रुपये किराया कर दिया गया जिसके कारण आम जनमानस को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली में 2004 व 2009 में दो बार मेट्रो के किराए बढ़ाए गए थे।
- मेट्रो किराए बढ़ने के कारण मेट्रो से चलने वाले यात्री जून 2016 में 25.7 लाख रह गए जबकि मई में इन यात्रियों की संख्या 26.5 लाख थी अर्थात 0.8 लाख यात्रियों की कमी आई। और यह कमी अक्टूबर में 24.2 लाख रह गई जबकि सितम्बर में यह संख्या 27.4 लाख थी। क्योंकि सितम्बर में दोबारा किराए बढ़ाए गए थे। अक्टूबर में 11 प्रतिशत यात्रियों की कमी यह दर्शाती है कि यात्रियों यात्रा के लिए दूसरे वाहनों का इस्तेमाल शुरु कर दिया है जिसके कारण अक्टूबर–नवम्बर 2017 में प्रदूषण का स्तर उच्च स्तर पर रहा।
- मेट्रो के फेयर फिक्सेसन कमेटी में आप पार्टी की दिल्ली सरकार तथा भाजपा की केन्द्र सरकार दोनो के प्रतिनिधि थे। जिन्होंने किराया बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनो सरकारों ने एक दूसरे पर राजनीति के चलते दिखावे के लिए आरोप–प्रत्यारोप लगाए थे।
- अक्टूबर 2017 के मेट्रो के किराए वृद्धि के कारण डीएमआरसी का संभावित वार्षिक राजस्व 755.92 करोड़ बढ़ जाता यादि दिल्ली और केन्द्र सरकार मेट्रो को 755.92 की सब्सिडी देने पर राजी हो जाते और दिल्ली मेट्रो से चलने वाले यात्रियों की प्रतिदिन 3 लाख कमी न होती परंतु दोनो केन्द्र व केजरीवाल सरकार दोनो ने इस दिशा में कोई भी कदम उठाने में नाकामयाब रहीं।

आप पार्टी सरकार का महत्वपूर्ण परिवहन प्रोजेक्ट को लेकर ढुलमुल रवैया

- **मेट्रो फेस–III** अपनी समय सीमा से पीछे चल रहा है जिसमें 2 वर्ष की देरी होगी। फेस–3 केन्द्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 9.8.2011 को मंजूर किया था जिसके बाद तुरंत ही काम शुरु हो गया था। इस फेस के अन्तर्गत सितम्बर 2016 तक 156 किलोमीटर पूरा होना था परंतु समय सीमा पर केवल 22 किलोमीटर का काम ही पूरा हो सका। जिसके कारण लागत राशि बढ़ी और फेस–3 के लेट होने के कारण किराए भी बढ़े।

Total Estimated Delay in proposed lines of Phase-III			
Corridor	**Initial Target date of Completion**	**Revised Date of Completion**	**Delay**
1.Mukundpur - Shiv Vihar	March, 2016	April, 2018	**2Yr.**
2.Janakpuri west Munirka - Kalka Ji - Kalindikunj	February, 2016	December, 2017	**10Month**
3. Central Sectt. - Mandi House - Kashmiri Gate	December, 2015	Commenced	
4.Jahangirpuri - Badli	March, 2015 Phase wise	Commenced	
5.Dwarka - Najafgarh	December, 2015	December, 2018	**3Yr.**
6.Delhi Portion of Bahadurgarh (Mundka to Bahadurgarh)	March, 2016	December, 2018	**2Yr. 8 Months**

- **Source : Delhi Government Plan Documents**

- **मेट्रो फेस–4 प्रोजेक्ट एक साल से लटका हुआ है :** दिल्ली शहर का महत्वकांक्षी फेस–4 प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार के वित्तिय कारणों की वजह से 1 वर्ष लटका हुआ है यदि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो न सिर्फ दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि 20 लाख वाहन सड़कों से हट जाऐंगे तथा 19 लाख टन वार्षिक प्रदूषक कम होंगे। डीपीआर एप्रूवल के लिए फाईल 2014–15 में जमा हो गई थी जबकि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में घूम रही हैं। अगस्त 2017 में नई मेट्रो पॉलिसी आ चुकी है और ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार नई पॉलिसी की शर्ते पूरी करने में कामयाब होगी।

- **दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर** : दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रोक रखा है क्योंकि दिल्ली सरकार और नेशनल केपिटल रीज़न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के बीच में फ्रेश फंडिंग पेटर्न का मामला है क्योंकि उसको आर.आर.टी.एस के द्वारा लागू किया जाना है। यह छोटा से मुद्दा है परंतु सरकार ने जानबूझ कर इस फाईल का दबा रखा है।

- 36 प्रतिशत यात्री दिल्ली और मेरठ के बीच में चलते है जो कि कार का इस्तेमाल करते है, 32 प्रतिशत यात्री सब–अरबन रेलवे तथा 27 प्रतिशत अपने दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते है। यदि दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो कारों के इस्तेमाल में 22 प्रतिशत, दुपहिया वाहनों में 15 प्रतिशत की कमी आ जाएगा और 46 प्रतिशत के करीब यातायात दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिफ्ट हो जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से 7 लाख यात्री इससे यात्रा करेंगे। जिसके कारण प्रदूषण में कमी आएगी।

बसों के बेड़े में बसों को न जोड़ने का आप पार्टी की दिल्ली सरकार का बहाना

दिल्ली सरकार डीटीसी के बेड़े में और नई बसें न जोड़ पाने का बहाना यह बना रही है कि डीटीसी/दिल्ली सरकार के पास नई बसों के लिए पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नही है। जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार के पास 1600–2000 बसें खड़ी करने के लिए जगह उपलब्ध है। जबकि बाकी बसें पहले से स्थापित डिपों में मल्टी लेवल पार्किंग के द्वारा खड़ी की जा सकती है।

- दिल्ली सरकार ने 2013–14 से लो–फ्लोर बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी नही किया है।
- आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने यह झूठा बहाना बना रही थी कि 2021 के मास्टर प्लान में किए जाने वाले संशोधन के चलते दिल्ली सरकार मल्टी लेवल पार्किंग नही बना सकती। जब ई.पी.सी.ए. की रिकोमेन्डेशन पर 2016 में मास्टर प्लान में संशोधन करके मल्टी लेवल पार्किंग को जोड़ दिया गया। अब सरकार इस मुद्दे का निरीक्षण करने का बहाना बना रही है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त Environment Pollution Control Authority (EPCA) ने सरकार व डीटीसी को मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस बनाने रिकोमेन्डेशन दी थी जबकि दिल्ली सरकार एवं डीटीसी इसके विरोध में है। दिल्ली सरकार और डीटीसी यह कह रहे है कि मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस कोस्ट इफेक्टिव नही होगी। जबकि इपीसीए के अनुसार परम्परागत रुप में ग्राउंड बस डिपों में कुल लागत (Land + Construction) प्रत्येक बस पर 32.29 लाख/बस आएगा जबकि यदि पहले से स्थापित बस डिपों को मल्टी लेवल डिपों में बदला जाता है तो वह 29.95 लाख/बस आऐगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इपीसीए के सुझावों पर ध्यान नही दे रही है।
- सितम्बर 2017 तक बवाना सेक्टर 1 में 3.75 एकड़ जमीन है। रेवला खानपूर साउथ वेस्ट जिला में 4 एकड़ जमीन है। इनमें 9096 बसों की पार्किंग क्षमता है। डिपो तैयार हैं और नई बसें न आने के कारण चालू नही हुए है।
- एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि जगह न मिलने के कारण वे बसों के बेड़े में नई बसें नही जोड़ रहे है। जबकि महरौली बस डिपो की मरम्मत पैसे के कारण नही कर रहे है।

उपलब्ध राशि का प्रयोग न करना।

- **JNNURM के तहत आप पार्टी की दिल्ली सरकार को 205 करोड़ का फंड मिलना था जो कि इनकी लापरवाही से नही मिल सका :** भारत सरकार ने अगस्त 2013 में एक योजना लागू की थी जिसके तहत JNNURM **योजना के अन्तर्गत** Urban Bus Specifications-II (UBS-II) की बसों की कुल लागत का 35 प्रतिशत फंडिंग केन्द्र सरकार से होनी थी। जिसके लिए दिल्ली सरकार को 31 मार्च, 2014 से पहले राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की अप्रूवल के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) भारत सरकार को भेजनी थी। डीपीआर के जमा करने में देरी के कारण निगम को केन्द्र सरकार से बस खरीदने के लिए 204.57 करोड़ की धनराशि जो कि सहायता के रुप में मिलनी थी वह नही मिल पाई। जबकि निगम ने 25 लाख रुपये सीआईआरटी को प्रोपोजल की कंसलटेन्सी के दे दिए जो कि बर्बाद हो गए।

- **पर्यावरण मुआवजा शुल्क (Environment Compensation Charge) को खर्च न कर पाना :** दिल्ली में परिवहन व्यवस्था जर्जर हालत में है परंतु सरकार ने Environment Compensation Charge के तहत 829 करोड़ रुपया माल ढ़ोने वाले वाहनों से एकत्रित किया जिसमें से केवल 93 करोड़ रुपया ही खर्च किया जा सका। यह राशि 6 नवम्बर 2015 से 1 नवम्बर 2017 के बीच एकत्रित की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसके तहत एकत्रित की जाने वाली राशि को सड़कों, सार्वजनिक परिवहन तथा साईकिल ट्रेक बनाने के लिए खर्च किया जाना था।
- **निर्भया फंड से 140 करोड़ रुपया जो कि डीटीसी तथा कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों के लिए लेने में असफलता:** दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने केन्द्र सरकार की महिला एवं बाल कल्याण

विकास मंत्रालय से निर्भया फंड के अन्तर्गत डीटीसी तथा कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों लगाने के लिए 2017–18 में सीसीएस के तहत राशि के लिए अनुरोध किया था। सरकार ने 20.6.2017 के केबिनेट के फैसले 2483 के द्वारा 6,350 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने थे और प्रत्येक डीटीसी व कलस्टर बसों में तीन सीसीटीवी कैमरे लगने थे जिससे कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परंतु आप पार्टी की केजरीवाल सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण गृहमंत्रालय ने उनके प्रोपोज़ल को ठुकरा दिया।

प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (PUC) की असफलता

- दिल्ली में 971 प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र है परंतु परिवहन विभाग के पास केवल 28 इंस्पेक्टर हैं परंतु एक ही इंस्पेक्टर, जो जमीनी स्तर पर इतने सारे केन्द्रों की जांच करने लिए उपलब्ध है।
- एक तरफ तो अरविन्द केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का दावा करते है परंतु प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र में भ्रष्टाचार के कारण वाहनों का प्रदूषण बढ़ा है जिसमें नकली सोफ्टवेयर के द्वारा झूठे पास बनाए जाते है तथा गलत टेस्टों को भी पास किया जाता है। ईपीसीए के विश्लेषण के अनुसार 13.7 लाख के एमीश्न आंकड़ों में से 20 प्रतिशत टेस्ट में प्रदूषकों की 0 वैल्यू मिली है, जो कि इस कार्यक्रम की कार्यकुशलता और सरकार के लाईसेंसिग प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- **कार्यक्रम की कमजोर अनुपालनाः** 1 नवम्बर 2016 से 31 जनवरी 2017 के बीच के उपलब्ध आंकड़ो पर आधारित ईपीसीए की रिपोर्ट यह बताती है कि 23 प्रतिशत वाहन ही सिर्फ टेस्ट के लिए आए। जो सरकार की नाकामी को बताता है, जबकि 100 प्रतिशत वाहनों का टेस्ट होना चाहिए।
- **फेल होने की दर बहुत कम – तकरीबन सभी वाहन पास :** जो वाहन टेस्ट के लिए आते है उनमें फेल होने की दर बहुत कम है। केवल 1.68 प्रतिशत डीजल के वाहन स्मोक डेन्सिटी टेस्ट पर फेल हुए हैं और 4.5 प्रतिशत पेट्रोल के वाहन CO तथा HC टेस्ट पर फेल हुए है। इस प्रकार यह कार्यक्रम इतना सक्षम भी नही है कि 15 से 20 प्रतिशत उन वाहनों को पकड़ पाए जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते है।

आम आदमी पार्टी के 2015 के घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण वायदे तथा उनकी सच्चाई :

❖ **AAP का वायदा : हम एक यूनाईफाईड ट्रांसपोर्ट अथारिटी बनाऐंगे जिसके तहत मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा, रिक्शा तथा साईकिल को लेकर होलिस्टिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाऐंगे ।**

सच्चाई :सिंगल अथॉरिटी बनाने की समय की मांग है ताकि आंतरिक सिस्टम को दुरस्त किया जा सके। जैसा कि नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी ने सुझाव दिया था। परंतु आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 3 वर्ष के बाद इस ओर एक कदम भी नही बढ़ाया है।

❖ **वायदा : ऑटो स्टेंड , ऑटो रिक्शा की खरीद को दुरस्त करके उसमें ब्लैक मार्केटिंग को रोकना तथा ऑटो वालों को लेकर पुलिस जादतियों को रोकना था।**

सच्चाई : एक भी नया ऑटो स्टेन्ड चिन्हित नही किया गया, ऑटो रिक्शा की खरीद को दुरस्त करने की बजाए सरकार प्रोसेस पूरा होने के बाद नियमों में बदलाव किया। कानून की धज्जियां उड़ाई गई और ऑटो परमिट जान बूझकर 80 प्रतिशत परमिट ऑटो रिक्शा फाईनेन्स माफिया को बांटे गए। ऑटो माफिया ऑटो परमिट को भारी मात्रा में खरीदता है और उसको मनमाने दामों पर बेचता है। ऑटो ड्राईवर पुलिस के द्वारा परेशान किए जाते है।

❖ **वायदा : हम डीटीसी के कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करेंगें। डीटीसी के बहुत सारे कर्मचारियों का अनुबंधित प्रथा के कारण शोषण हो रहा है। हम अनुबंध पर रोजगार को खत्म कर देंगे।**

सच्चाई : आप पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है क्योंकि डीटीसी के अनुबंधित कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के बाहर नियमितकरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग के लिए धरना देते है। आप पार्टी ने अपने 49 दिन के 2014 के कार्यकाल में यह वायदा किया था कि वे उनको नियमित करेंगे, और यह वायदा उन्होंने 2015 के घोषणा पत्र में भी किया। परंतु 3 वर्ष के शासन के बावजूद भी अपना यह वायदा पूरा नही किया है।

❖ **वायदा : हमने मेट्रो के विस्तार के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है।**

सच्चाई : आप पार्टी की सरकार ने मेट्रो फेस–3 के प्रोजेक्ट को 2 साल से अधिक पीछे कर दिया है जबकि मेट्रो फेस–4 का कोई पता नही है।

❖ **वायदा : वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों तथा विकलांगों को बसों व मेट्रो में रियायत दी जाएगी।**

सच्चाई : 4th FFC जिसमें एक सदस्य दिल्ली सरकार से होता है उन्होंने दिल्ली मेट्रों मे रियायती दर के मामले का परीक्षण किया और यह पाया कि नेटवर्क में इस प्रकार की व्यवस्था तकनीकी रुप से तैयार नही है।

❖ **वायदा :** हम ऑटो के किराए में मंहगाई के अनुसार प्रतिवर्ष दो बार की वृद्धि करेंगे तथा मीटर में वेटिंग शुल्क भी लागू होगा।

सच्चाई : आम आदमी पार्टी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात ऑटो किराए में कोई वृद्धि नही हुई है जबकि पिछली बार दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 4.5.2013 को किराया बढ़ाया था।

❖ **वायदा : हम** धारा 66/192ए के गलत इस्तेमाल को रोकेंगे।

सच्चाई : ऑटो में यात्रियों के साथ सामान ले जाने और पैसेंजर ऑटो में सामान ले जाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192ए में अपराध है। परिवहन उप निरीक्षक इन धाराओं का इस्तेमाल करते है, इसके बावजूद ऑटो वालों के पास परमिट व अन्य दस्तावेज होते है। उसके बावजूद थी उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के शासन में इस धारा का गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा है।

आप पार्टी ने बिगाड़ी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था

पिछले तीन वर्षों में पानी से फैलने वाली बीमारियों ने दिल्ली में बहुत तेजी से पैर पसारे है और दिल्ली सरकार इन बीमारियों की रोकथाम करने में विफल रही है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए बड़े–बड़े वायदों की हवा निकली है क्योंकि बीमारियों का प्रकोप दिल्ली पर प्रतिवर्ष आता है। पिछले साल भी दिल्ली में डेंगू के 9,072 मामले सामने आए थे। आप पार्टी की दिल्ली सरकार की किसी भी समस्या के पहले से निदान और उसका प्रबंधन करने की विफलता सबको पता चल चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में बीमार लोगों की आपार भीड़, फर्शों और बरामदों में पड़े हुए लोग, अस्पताल के बाहर इंतजार करते मरीजों की दशा दिल्ली के नागरिकों को परेशान करती है। जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता संभाली है दिल्ली का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है।

- आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस द्वारा शुरु किए गए अस्पतालों के प्रोजेक्ट को पूरा करने का वायदा किया था परंतु इस सरकार ढुलमुल रवैय के कारण जिन अस्पतालों के प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके है उन्होंने भी काम करना शुरु नही किया है।
- आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 30,000 बेड बढ़ाने की बात की थी परंतु 2014 से अब तक केवल 806 बेड ही बढ़ाए गए है। अर्थात 268 बेड प्रतिवर्ष की औसत निकलती है। उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल 2008 से 2013 तक 544 बेड प्रति वर्ष की औसत से बेड बढाए गए थे
- **बजट में डेढ गुणा की बढ़ौतरी का झूठा दावाः** 25 जनवरी 2017 को राज्य के गंणतंत्र दिवस के उपलक्ष में विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के सामने अरविन्द केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झूठ बोला था और यह दावा किया था कि उनकी सरकार ने अपने पहले ही बजट यानि 2015–16 में स्वास्थ्य के बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पार्टी ने इस विषय को लेकर पूरी दिल्ली में झूठे पोस्टर और बैनर भी लगाए।
- यदि हम 2015–16 के actual plan expenditure को पिछले वर्ष के expenditure से मिलाऐ तो झूठ सामने आता है। यदि हम आम आदमी पार्टी सरकार के घटते हुए expenditure को पिछले वित्त वर्ष से तुलना की जाए तो पहले ही वर्ष में 112 करोड़ रुपये खर्च कम हुए है। 46 प्रतिशत धन राशि बिना खर्च किए रह गई। दूसरे वर्ष में आवंटन बढ़ा परंतु खर्च की गई राशि कम हुई। अर्थात 44 प्रतिशत धनराशि बिना इस्तेमाल किए गई। यह रुझान लगातार चलता रहा जिसमें तीसरे साल सितम्बर 2017 तक आंकड़े उपलब्ध हैं। 2017–18 का बजट एलोकेशन पिछले वर्ष की तुलना में कम है। खर्च की जाने वाली राशि भी बहुत कम है। 2017–18 के वित्त वर्ष के 6 महीने बीत चुके है और सितंबर 2017 में केवल 25 प्रतिशत राशि खर्च हुई।

EXPENDITURE BY DELHI GOVERNMENT ON MEDICAL&HEALTH			
Financial Year	**Allocation**	**Expenditure**	**% Non-Utilization of Allocated Fund**
2014-15	2390Cr	2124Cr	**11%**
2015-16	3138Cr	2012Cr	**36%**
2016-17	3200Cr	2096Cr	**34%**
2017-18	2627Cr	666Cr(Till Sep'17)	**75%(Till Sep'17)**

Source : Planning Government website

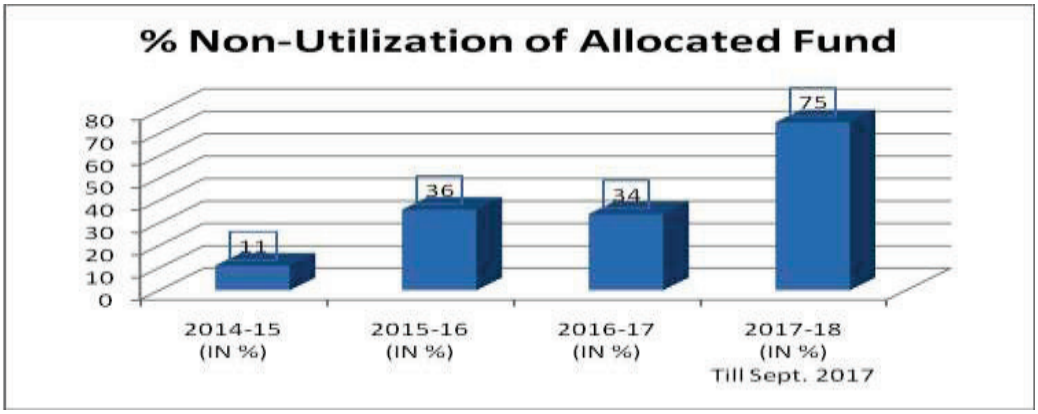

दिल्ली में डिस्पेन्सरियां

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने डिस्पेन्सरियों की संख्या जो कि 602 छोड़ी थी उसको आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने 2016–17 में कम करके 491 कर दिया। आप पार्टी के कार्यकाल में कुल 111 डिस्पेन्सरियां बंद कर दी गई और 24 डिस्पेन्सरियों को पोलिक्लीनिक में बदल दिया।

- आप पार्टी के कार्यकाल में कुल 111 डिस्पेन्सरियां बंद हुई
- 24 डिस्पेन्सरियों को पोलीक्लीनिक में बदला गया।

Dispensaries	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Allopathic	260	260	242	245
Mobile Health Clinic	90	43	43	24
School Health Clinic	100	72	70	59
Homeopathic	100	101	101	103
Ayurvedic	35	36	39	40
Unani	17	18	19	20
Total Dispensaries	**602**	**530**	**514**	**491**

Source: Annual Report 2016-17,DGHS Delhi Gov.

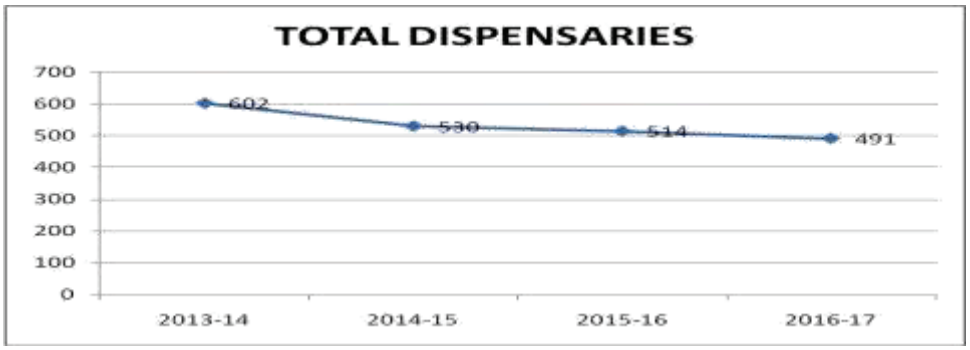

New Dispensaries opened during last 4yr.: Congress Govt. opened 12 dispensaries

FY	Allopathic	Homeopathic	Ayurvedic	Unani	Total
2013-14	4	5	2	1	**12**
2014-15	0	1	1	1	**3**
2015-16	3	1	3	2	**9**
2016-17	1	2	1	1	**5**

during 2013-14 in a single year, while AAP opened 14 outlets during last three year.

Source: Data Compiled from Annual Report of DGHS Delhi Gov.

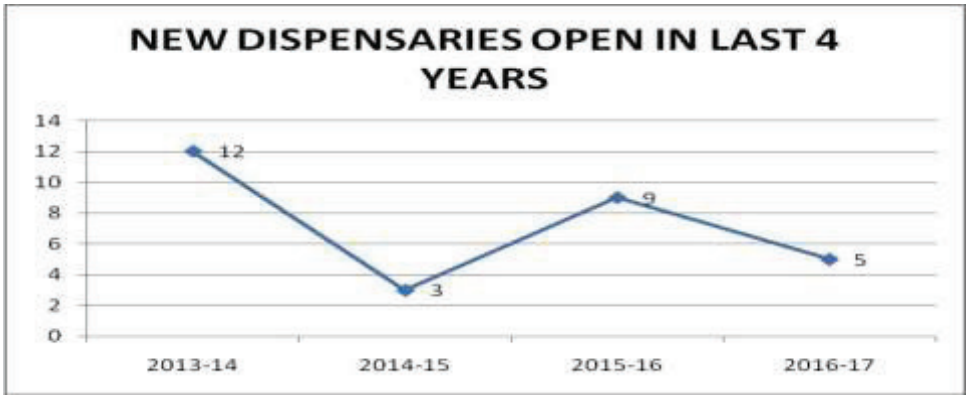

आम आदमी पार्टी स्कूल व मोबाईल हैल्थ क्लीनिक को बंद करने की तैयारी में

मोबाईल हैल्थ क्लीनिक तथा स्कूल हैल्थ क्लीनिक में मरीजों की उपस्थित जो 2013–14 के मुकाबले 2016–17 में 91 प्रतिशत कम हुआ है। स्कूल हैल्थ स्कीम में 2015–16 में 58 प्रतिशत की कमी आई है। जिसके हिसाब 2016–17 में कुछ सुधार हुआ है परंतु इसके बावदजूद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जितनी उपस्थिति थी उससे बहुत पीछे है।

OPD Attendance in School and Mobile Health Clinics during last 4Yrs.				
Dispensaries	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
Mobile Health Clinic	14,97,683	8,06,188	4,80,346	1,40,215
School Health Clinic	1,24,934	63,507	53,001	1,22025

Source: Data Compiled from Annual Report of DGHS Delhi Gov.

स्कूल हैल्थ स्कीम के तहत विद्यार्थियों के लेब टेस्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बहुत कम है और इसमें 98 प्रतिशत की गिरावट आई है। मोबाईल हैल्थ स्कीम के बारे में दिल्ली सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 में कोई जिक्र नही है।

Lab Tests in School and Mobile Health Clinics				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Mobile Health Clinics	3704	1330	201	-
School Health Clinics	510131	640859	26,70,43	10234

स्कूल हैल्थ स्कीम की कमिया :

- 1218 सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रतिवर्ष 300 स्कूल ही इस स्कीम के तहत फायदा उठा पाते है क्योंकि मानव संसाधन सीमित है।
- 12 मेडिकल ऑफिसर इस स्कीम के जिलों के इंचार्ज के रुप में काम कर रहे है।
- कई स्कूल हैल्थ सेन्टर बिना मेडिकल ऑफिसर और बिना पी.एच.एन. के चल रहे है। बहुत कम क्लीनिक है जिनमें डाक्टर या पीएचएन–3 हैं।
- दिन प्रति सप्ताह के हिसाब से है।
- अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक इन सेन्टरों में लेब टेक्नीशन/लेब असिसटेन्ट नही थे जो खून की जांच कर सकें।
- 2 से 3 क्लीनिक में एक फार्मासिस्ट है।
- ये सेन्टर 53 रह गए है क्योंकि इन सेन्टरों में कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मोबाईल हैल्थ स्कीम की कमियां :

- मोबाईल वैन जो कि जे.जे. कलस्टर/निर्माणाधीन जगहों इत्यादि पर स्वास्थ्य सेवाएं देती थी उनकी संख्या 2013–14 में 90 थी जबकि सितम्बर 2017 में एक भी मोबाईल वैन नही है।
- डाक्टर तथा उनकी टीम क्षेत्रों में अपनी सुविधा के हिसाब से जाती है क्योंकि गाड़ियों की खरीद के लिए अनुमति अभी तक नही मिली है।
- स्टाफ की वेकेन्सियां जो कांग्रेस की सरकार के समय 2013–14 में 48 थी वह अब 2016–17 में 180 है।

मौहल्ला क्लीनिक का भंडाफोड़:

पहले से स्थापित डिस्पेन्सरियों के विस्तार तथा उनको मजबूत करने की जगह आम आदमी पार्टी ने 1000 मौहल्ला क्लीनिक बनाने की बात कही थी जिसका हमने स्वागत किया, परंतु यह एक घोषणा थी। सरकार की कोई दूरदर्शिता नही है। सरकार ने इसको पॉयलट प्रोजेक्ट के रुप में शुरु किया परंतु अभी तक सरकार मौहल्ला क्लीनिक को लेकर ठोस योजना नही बना पाई है।

- 3 वर्ष बीत चुके है परंतु अभी तक केवल 162 मौहल्ला क्लीनिक खोले गए है जबकि आप पार्टी ने 1000 मौहल्ला क्लीनिक खोलने का वायदा किया था। 102 मौहल्ला क्लीनिक किराए की बिल्डिंगों में चल रहे है।
- दिल्ली सरकार को पहले ही 561 मौहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए एनओसी मिल चुका है परंतु केवल 53 मौहल्ला क्लीनिकों का काम पूरा हुआ है। पहले से पुरे हुए क्लीनिक चालू नही किए जा रहे है क्योंकि कर्मचारियों की कमी है।
- पहले से स्थापित मौहल्ला क्लीनिक, पोलीक्लीनिक तथा डिस्पेन्सरियों में कर्मचारियों की कमी है। स्वास्थ्य की 25 प्रतिशत, सेन्शन पोस्ट तथा 61 प्रतिशत नान मेडिकल की पोस्ट खाली हैं।
- सरकार ने बड़े–बड़े विज्ञापनों के द्वारा यह दावा किया था कि मौहल्ला क्लीनिकों में 200 प्रकार के टेस्ट किए जाते है। परंतु सच्चाई यह है कि पश्चिम तथा नई दिल्ली के मौहल्ला क्लीनिकों में खून की

जांच 2015–16 के दौरान होती थी। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2016–17 में दिल्ली के पांच जिलों में पेशाब तथा खून के टेस्ट होते थे, बाकी जिलों में लेब की सुविधा नही है। या उन्होंने दिल्ली सरकार को नही बताया।

- मौहल्ला क्लीनिकों के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह मार्केट रेंट से बहुत ज्यादा की दरों पर किराए पर ली गई हैं।
- कई मौहल्ला क्लीनिक गंदे है और जहां पर न तो बैठने की पर्याप्त जगह है और दूसरी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नही है तथा भीड़ भी ज्यादा होती है।
- एक आरटीआई के द्वारा यह उजागर हुआ कि एक मौहल्ला क्लीनिक में 4 घंटों में एक डाक्टर को 533 मरीज देखने की रकम का भुगतान हुआ। अर्थात 36 सैंकड में एक मरीज देखा गया जिससे साफतौर पर घोटाला नजर आता है।
- मौहल्ला क्लीनिकों में प्राईवेट डाक्टरों की सेवाएं ली जा रही है और एक डाक्टर औसतन 4 घंटे प्रतिदिन सेवाएं देकर 75 हजार से 1 लाख रुपया प्रतिमाह कमा रहा है। जबकि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों को इनसे कम वेतन मिलता है जबकि इन डाक्टरों को 12 या उससे ज्यादा समय प्रतिदिन नौकरी करनी पड़ती है।
- मौहल्ला क्लीनिक के डाक्टरों के पास महामारियों से निपटने के लिए कोई सुविधाएं नही है और वे सिर्फ ओपीडी सपोर्ट दे सकते है।

डेंगू और चिकनगुनिया का कहरः

डेंगू के मामलों और मृत्युदर में बहुत बढ़ौत्तरी : आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि वे दिल्ली से डेंगू को जड़ से खत्म कर देंगे। परंतु आम आदमी पार्टी के पहले वर्ष के कार्यकाल यानि 2015 में ही डेंगू के मामलों में 185 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी कांग्रेस की सरकार 2013 की तुलना में हुई। मृत्यु दर में भी आप पार्टी के शासन में 900 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हुई है।

Year	2011	2012	2013	2014	2015
No. of Dengue Cases	1,131	2,093	5,574	995	**15,867**
No. of Reported Death	8	4	6	3	**60**

Source: CAG Report

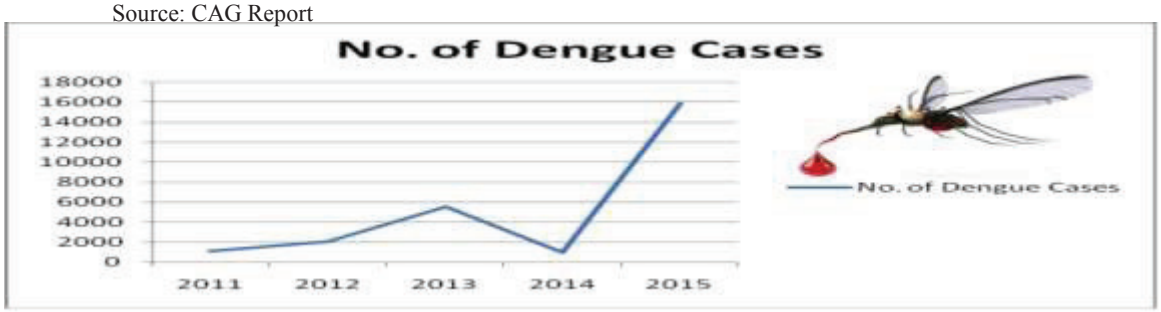

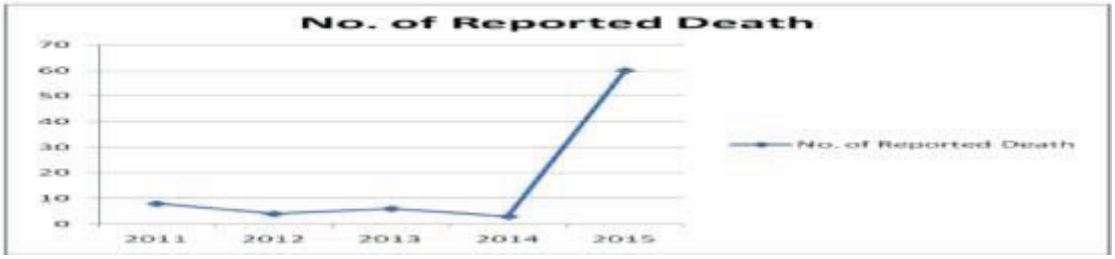

- आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की लापरवाही तथा अनदेखी के कारण 2016 में चिकनगुनिया के सस्पेक्टेट केसों में बेहताशा वृद्धि हुई है। जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिकनगुनिया दिल्ली से तकरीबन समाप्त हो गया था।

Year	2012	2013	2014	2015	2016
Chickengunia Cases	6	18	8	**64**	**11,192**

Source: Economic Survey of Delhi.

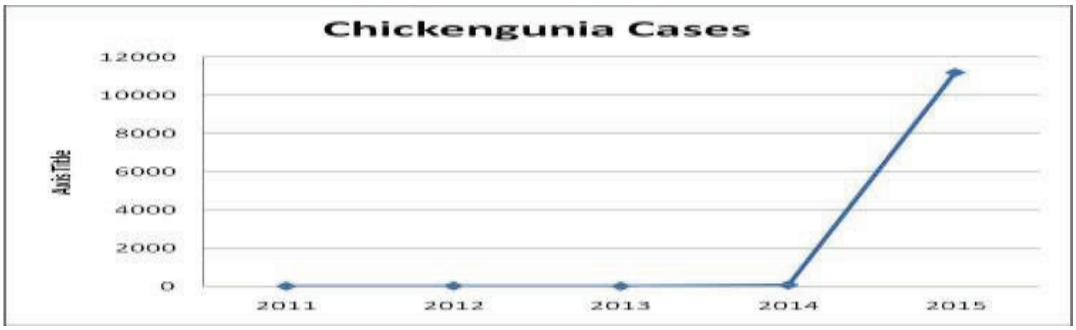

दिल्लीः स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती बीमारियां

दिल्ली में न सिर्फ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में बढ़ौतरी हुई है परंतु अन्य बीमारियों ने भी यहां पैर पसारे है।

- डायरियां तथा कोलेरा दोनो कई गुणा बढ़े है जो कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां है और गंदे पानी के कारण फैलती है। 2016 में 50 प्रतिशत शिकायतें पानी की सप्लाई तथा पानी की क्वालिटी को लेकर की गई थी। आंकड़ों के अनुसार आप पार्टी का मुफ्त व स्वच्छ पानी देने का वायदा झूठा साबित होता है।
- पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,85,480 लोग डायरिया से प्रभावित हुए है, कोलेरा के मामले जो 2014 में 2,524 थे वे 2016 में 190 प्रतिशत बढ़कर 7,328 हो गए। इसी प्रकार कोलेरा के कारण होने वाली मृत्यु जहां 2014 में 39 थी वे 2015 में बढ़कर 138 हो गई।
- एचआईवी/एड्स के मामले बेहताशा बढ़े है। 2014 में 2211 एचआईवी/एड्स के मामले सामने आए थे वे 684 प्रतिशत बढ़कर 2016 में 17,332 हो गए।

Table : Rapid Increase in Diseases During 'AAP' Govt. in Delhi

Diseases	No. of Cases in 2014	No. of Cases in 2016	% Increase during 2014-16
Cholera	2,524	7,328	**190%**
HIV/AIDS	2,211	17,332	**684%**
Diabetes	3,39,188	3,92,528	**16%**
Diarrhoea	5,82,152	6,22,480	**7%**
Hypertension	3,46,856	3,61,443	**4%**
Typhoid	42,866	54,589	**27%**
Other Diseases	2,75,30,127	3,22,18,416	**17%**

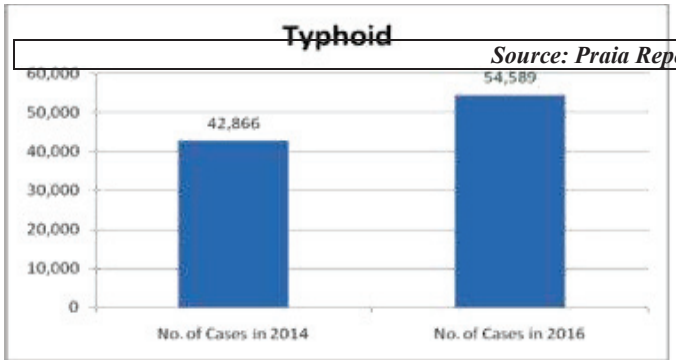

Source: Praia Report

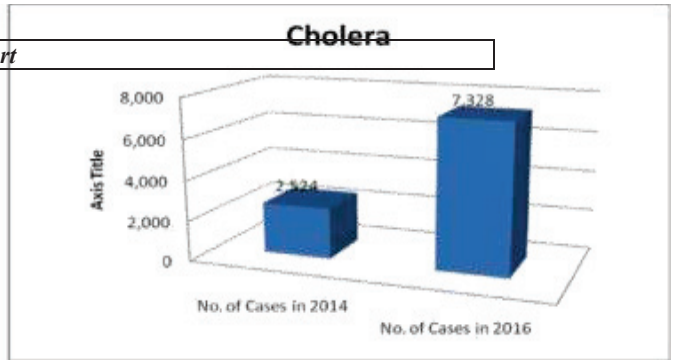

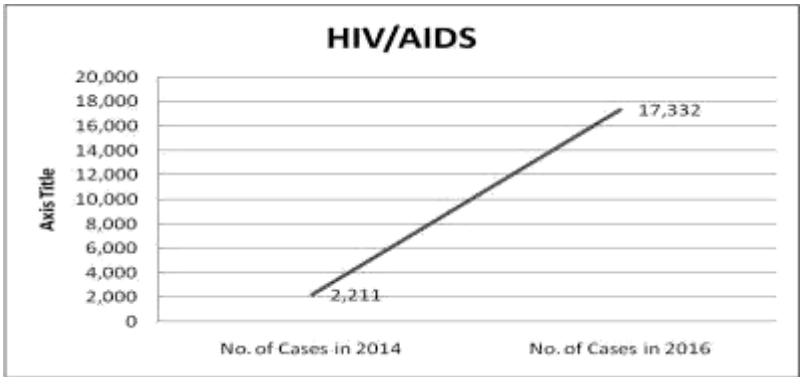

परिवार कल्याण योजनाएं

- कॉउसलिंग लेने वाली गर्भवती महिलाओं में कमी आई है, जहां उनकी संख्या 2014 में 1,68,808 थी वह 2016–17 में 1,24,759 रह गई।
- 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे जो कि दाखिल हुए थे उनकी संख्या में बढ़ौत्तरी हुई है। 2014 में जहां यह संख्या 3,962 थी वह 2016–17 में 8,223 हो गई।
- मातृ मृत्यु दर जो कि 2014–15 में 399 थी वह बढ़कर 2016–17 में 508 रह गई।

राज्य अवार्ड योजना

- राज्य स्तर पर मेडिकल तथा पेरामेडिकल स्टाफ को इसलिए अवार्ड दिए जाते है ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके और वे दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सके।
- 2008–2013 में कांग्रेस के कार्यकाल में 122 डाक्टरों तथा 276 पेरामेडिकल स्टाफ को अवार्ड दिए गए परंतु केजरीवाल सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में किसी डाक्टर को योजना के तहत कोई अवार्ड नही मिला।

तंबाकू नियंतत्रण कानून को लागू करना।

	Congress Gov.'s avg.	Avg. AAP Govt.	%Reduction
No of Public Place and Public Service Vehicle Inspected	56,000	6,000	**89%**
No of Person Fined under Public Places and Public Service Vehicle	9,700	650	**93%**
Source : Compiled From DGHS Annual Report			

सरकारी अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों में कर्मचारियों की कमी

दिल्ली में मेडिकल तथा नान मेडिकल कर्मचारियों की बहुत कमी है। 25 प्रतिशत मेडिकल की सेन्शन पोस्ट खाली है, इसी प्रकार 19 प्रतिशत नर्स तथा 31 प्रतिशत पेरामेडिकल की पोस्ट खाली है।

	Medical	Para Medical	Nurse	Admin	Labour
Delhi Govt. Dispensaries/ Hospitals	25%	31%	19%	41%	37%

Source: Praja Report

आम आदमी पार्टी के 2015 के घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण वायदे तथा 3 वर्ष के शासन के बाद उनकी सच्चाई :

❖ **वायदा : हैल्थकेयर पर कुल खर्च बढ़ाया जाएगा।**
सच्चाई : यह वायदा किया गया था कि हैल्थकेयर पर कुल खर्च बढ़ाया जाएगा परंतु सच्चाई यह है कि इसमें कमी आई है। 2014–15 में सरकार ने 2,124 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया था परंतु 2015–16 का आप पार्टी का खर्च 2,112 करोड़ तथा 2016–17 में यह 2,096 करोड़ रुपया हो गया। वित्त वर्ष 2017–18 में यह खर्च बहुत कम है और सितम्बर 2017 तक जब आधा वर्ष बीत चुका था उस समय यह खर्च केवल 666 करोड़ था।

❖ **वायदा : नए सरकारी अस्पताल खोले जाऐंगे ताकि हजार की जनसंख्या पर 5 बेड के अर्न्तराष्ट्रीय मापदंड को पूरा किया जा सके।**
सच्चाई : केजरीवाल सरकार ने नए अस्पताल खोलने की बजाए एक अस्पताल को बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में दिल्ली सरकार के 39 अस्पताल थे जो कि अब 38 रह गए है।

❖ **वायदा : हैल्थकेयर के ढ़ांचे में विस्तार होगा : आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 30,000 नए बेड जोड़ेगी जिसमें से 4000 बेड मेटरनिटी वार्ड में होंगे।**
सच्चाई : कांग्रेस सरकार ने 2013–14 में मेटरनिटी बेड की संख्या 435 तक बढ़ा दी थी जो कि केजरीवाल के समय यानि 2017 में शून्य हो गई है। जहां 30,000 नए बेड जोड़ने का वायदा था उसके जवाब में आप पार्टी की दिल्ली सरकार केवल 806 बेड जोड़ पाई अर्थात जो वायदा किया था उसका 3 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।

- **वायदा : डाक्टरों के 4000 पद तथा पेरामेडिक्स एवं नर्सों के 15000 पद वर्तमान में खाली है इन पदों को तुरंत भरा जाएगा। अनुबंध पर नियुक्तियां खत्म कर दी जाऐंगी :**
  सच्चाई : न तो डाक्टरों और न ही पेरामेडिक्स एवं नर्सों के खाली पदों को 3 वर्षों में भरा गया है।

- **वायदा : पिछले चुनाव में कई अस्पतालों का उदघाटन हुआ था परंतु ये प्रोजेक्ट पूरे नही हुए है हम इन आधे बने अस्पतालों को पूरा करेंगे।**
  सच्चाई : कांग्रेस सरकार के राज में विभिन्न अस्पतालों के निर्माण के प्रोजेक्ट नही चल रहे थे। इस सरकार के कार्यकाल में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बहुत कमजोर है।

- **वायदा : 900 नए प्राईमरी हैल्थ सेन्टर बनाए जाऐंगे।**
  सच्चाई : नए प्राईमरी हैल्थ सेन्टर बनाने की जगह सरकार ने पहले से चल रही 110 डिस्पेन्सरियों को ही बंद कर डाला।

- **वायदा : मौहल्ला सभा प्रथामिक अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन करेंगी तथा सरकार बड़े अस्पतालों की कार्यशैली को मोनिटर करेगी।**
  सच्चाई : दिल्ली में अभी तक मौहल्ला सभा नही है।

- **वायदा : डेंगू के बुखार को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। डेंगू को दिल्ली से खत्म करने के लिए हम अपने भरसक पर्यत्न करेंगे।**
  सच्चाई : आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में डेंगू के मामलों तथा उसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है।
- **वायदा : दिल्लीवासियों को लम्बे समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के कुशलता पूर्वक वितरण के लिए सभी दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाऐंगे।**
  सच्चाई : दिल्लीवासी स्वास्थ्य कार्ड का इंतजार कर रहे है।

#आम आदमी पार्टी शिक्षा के मामले में फेल

आप पार्टी के झूठे दावे बनाम सच्चाई

दावा : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बड़ी तेजी बढ़ा है।

सच्चाई : पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छात्रों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

- लगभग 1 लाख छात्रों ने दो साल में दिल्ली सरकार के स्कूल छोड़ दिए हैं।
- उसी समय प्राईवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या 1.42 लाख तक बढ़ गई।
- दिल्ली में सीनियर सेकेंड्री स्कूलों की वृद्धि केवल 0.60**%** ही हुई जो कि दिल्ली की जनसंख्या की औसत वृद्धि जो कि 2.42**%** है उससे बहुत कम है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

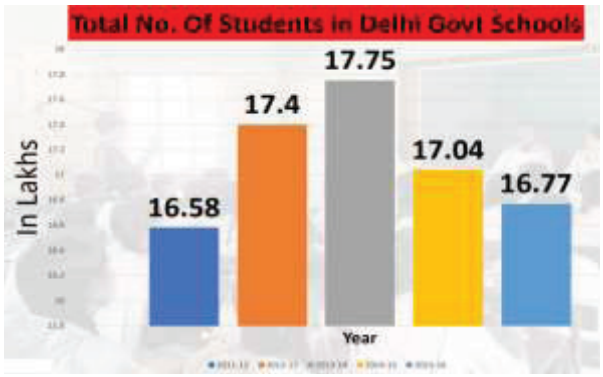

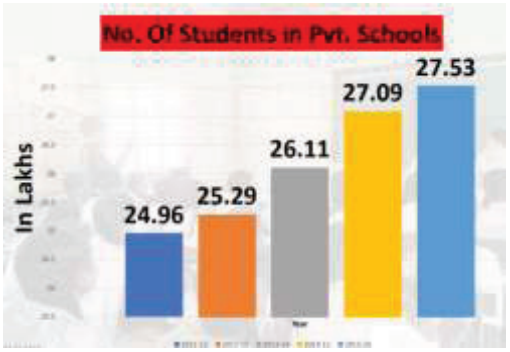

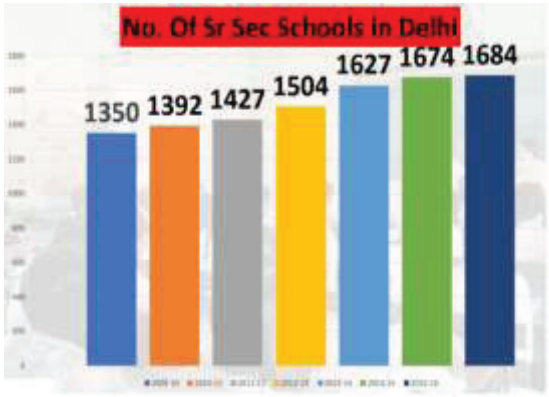

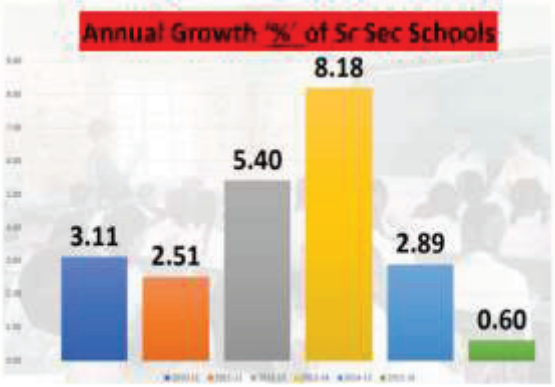

दावा : दिल्ली सरकार के 12वी और 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम अभी तक सबसे अच्छे

सच्चाई: कक्षा 10वी व 12वीं सीबीएसई बोर्ड के दिल्ली सरकार के स्कूलों के परिणाम अभी तक के समय में सबसे बुरे

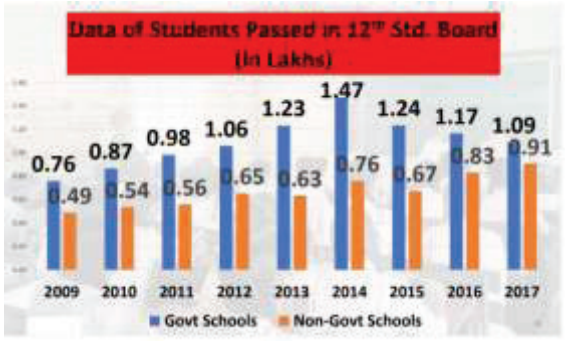

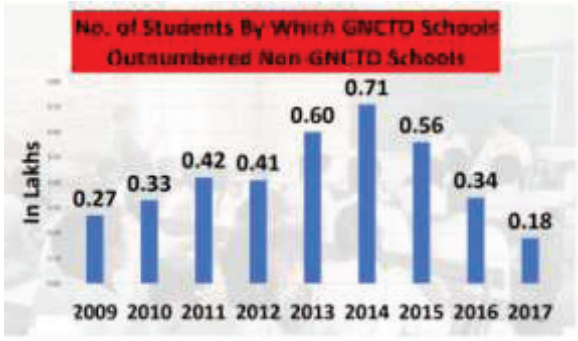

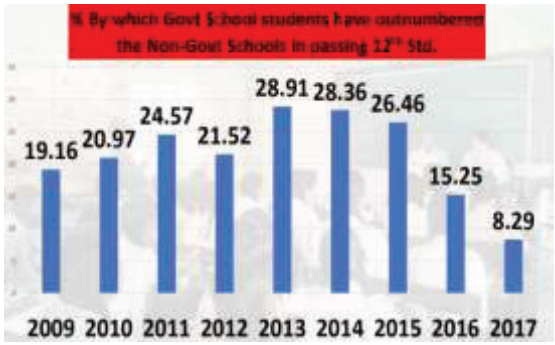

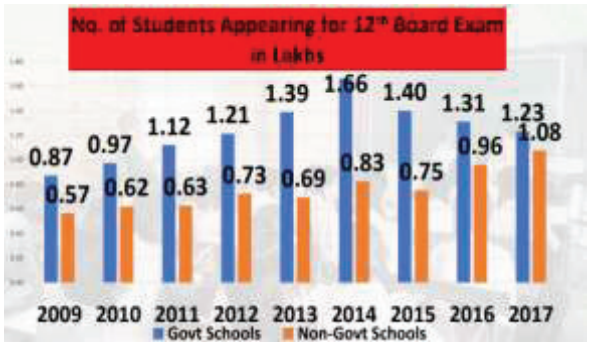

12वीं कक्षा

- इसके विपरीत– हाल ही के दिनों में सरकारी स्कूल के परिणाम सबसे ज्यादा खराब हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में छात्रों के उपस्थिति की संख्या 3 साल में 42,296 तक गिर गई है।
- दिल्ली सरकार के स्कूलों में सफल होने वाले छात्रों की संख्या 3 साल में 38,489 तक गिर गई है। (वर्ष 2014 और 2017 के बीच की तुलना के अनुसार)

10वीं कक्षा के बोर्ड के परिणाम अभी के समय के सबसे बुरे रहे है।

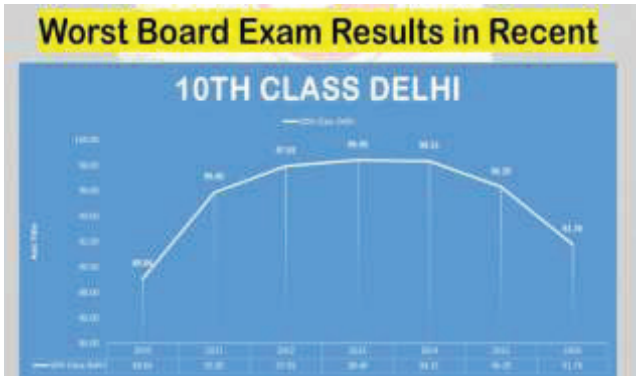

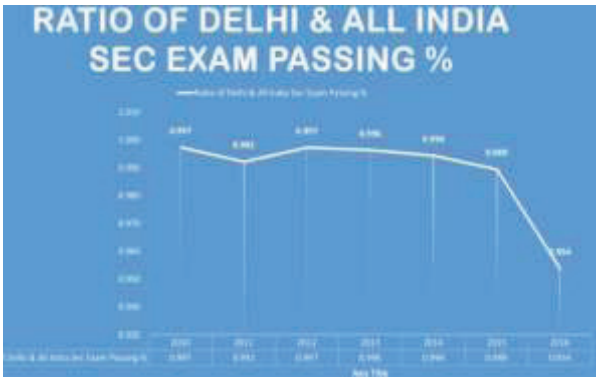

10 वीं कक्षा

- दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा का परिणाम औसत 98.40**%** से घटकर 91**%** हो गया है।
- **AAP** सरकार के अन्तर्गत, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से गंभीर कमी आई है। जबकि 2013 में (कांग्रेस के समय) दिल्ली में 10 वीं कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण अनुपात 1:996 था, जो 2016 में घटकर 1:959 रह गया है।

शिक्षा बजट

दावा : शिक्षा के बजट में ऐतिहासिक रिकार्ड बढ़ौतरी

सच्चाई : ऐतिहासिक रिकार्ड पैसा बिना खर्च हुए लैप्स हुआ।

- शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में 1,982 करोड़ रुपये बिना खर्च लैप्स हुआ है।
- यह दिल्ली में शिक्षा पर अभी तक बिना खर्च की गई सबसे ज्यादा राशि है।

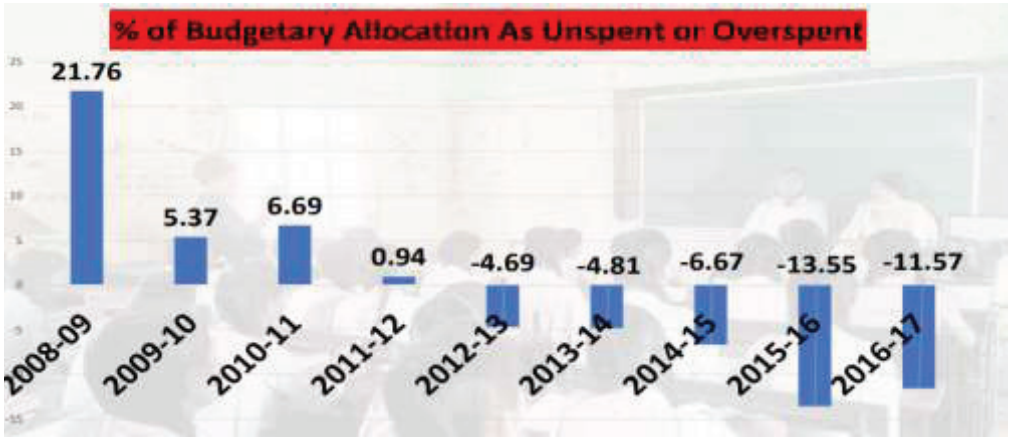

दिल्ली सरकार के स्कूलों में रिक्त पद

- दिल्ली सरकार के स्कूलों में 41.67% शिक्षकों के पद खाली हैं।
- दिल्ली विधानसभा में शिक्षा मंत्री के उत्तर के अनुसार, शिक्षा निदेशालय में 573 प्रींसीपलों के पद तथा 696 प्रींसीपलों की जगह वाईस प्रींसीपल उनका काम देख रहे है।

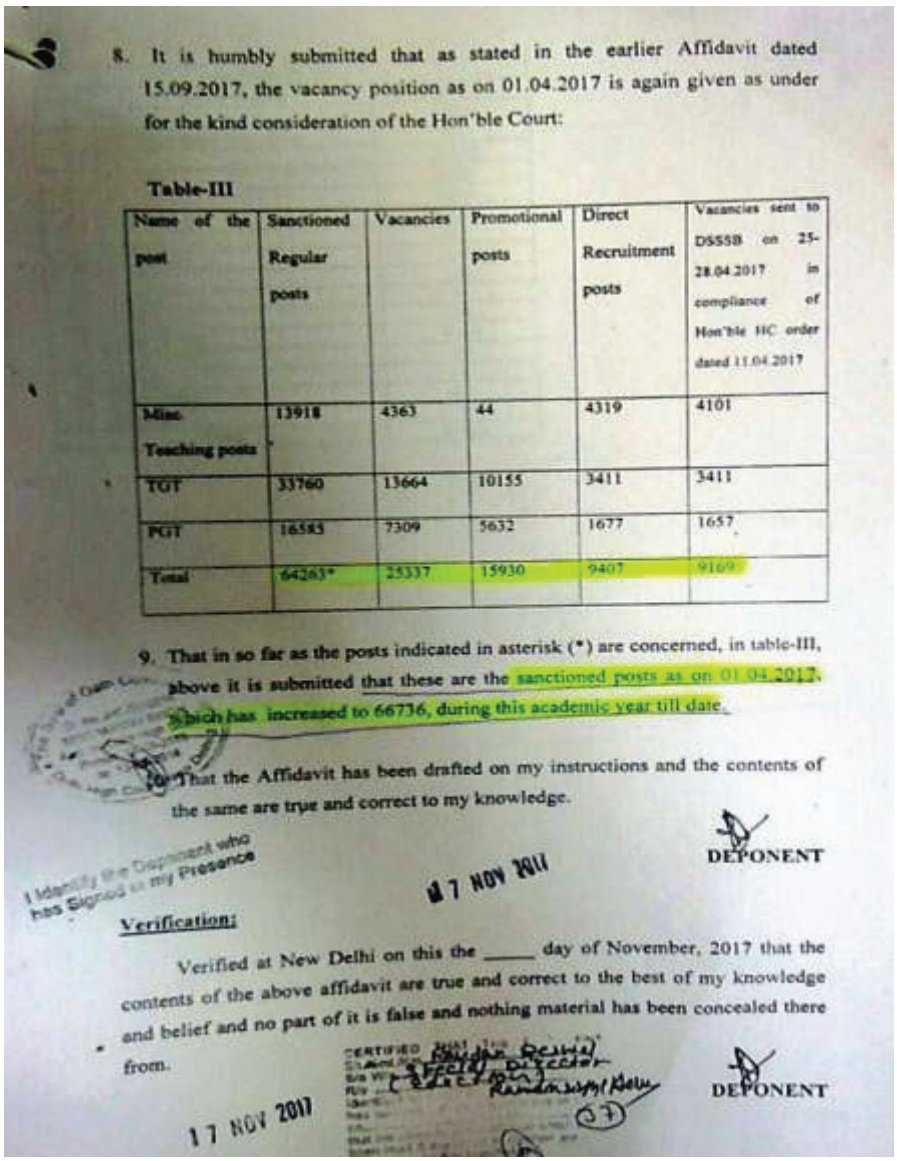

8. It is humbly submitted that as stated in the earlier Affidavit dated 15.09.2017, the vacancy position as on 01.04.2017 is again given as under for the kind consideration of the Hon'ble Court:

Table-III

Name of the post	Sanctioned Regular posts	Vacancies	Promotional posts	Direct Recruitment posts	Vacancies sent to DSSSB on 25-28.04.2017 in compliance of Hon'ble HC order dated 11.04.2017
Misc. Teaching posts	13918	4363	44	4319	4101
TGT	33760	13664	10155	3411	3411
PGT	16585	7309	5632	1677	1657
Total	64263*	25337	15930	9407	9169

9. That in so far as the posts indicated in asterisk (*) are concerned, in table-III, above it is submitted that these are the sanctioned posts as on 01.04.2017, which has increased to 66736, during this academic year till date.

That the Affidavit has been drafted on my instructions and the contents of the same are true and correct to my knowledge.

DEPONENT

I Identify the Deponent who has Signed in my Presence

17 NOV 2017

Verification:

Verified at New Delhi on this the ____ day of November, 2017 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

17 NOV 2017

DEPONENT

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार द्वारा 7 नवंबर, 2017 के शपथपत्र के अनुसार 07.12.2017 को शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 66,736 थी जिसमें से 27,810 रिक्त (01.04.2017 तक 25337 रिक्त पद थे) खाली थे।

आप पार्टी ने दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था।

झूठे वादे **V/S** वास्तविकता

Congress Gov. Opened more new schools compare to AAP

Year	No. of Gov Schools	New School
2011-12	948	14
2012-13	969	21
2013-14	992	23
2014-15	1007	15
2015-16	1009	2
2016-17	1017	8

Source : Final Baseline Data for 2030 of Delhi &Praga Report Dec. 2017

दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS श्रेणी की सीटें

कानून के मुताबिक दिल्ली में सभी निजी स्कूलों में **EWS** श्रेणी के छात्रों के लिए 31,000 सीटें आरक्षित हैं। अगर हम 2016–17 के आंकड़े लेते हैं, तो **EWS** कोटा में प्रवेश पाने के लिए 1.25 लाख फार्म भरे गऐ थे। हालांकि, केवल 20,000 बच्चों को ही एडमीशन मिला और निजी स्कूलों में 11,000 **EWS** की सीटें खाली रहीं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक शपथपत्र में उपरोक्त आंकड़ों की भी पुष्टि हुई है। भ्रष्टाचार का यह एक गंभीर मामला है । कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि क्या केजरीवाल और निजी स्कूलों के बीच क्या कोई समझौता हुआ है कि **EWS** श्रेणी की सीट खाली रखी जाए। क्या सीटों को खाली छोड़ने के लिए सरकार ने निजी स्कूलों से डोनेशन ली है?

#शहरी गरीबों को लेकर आम आदमी पार्टी की असफलता

शहरी संस्थागत ढ़ांचे को लेकर आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में निम्न वायदे किए थे :

1. **अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करना तथा उनमें बदलाव** : हम पुनर्वास कालोनियों में सम्पति व सेल–डीड करने के पंजीकरण के अधिकार देंगे। सरकार बनने के एक साल के अंदर ये अनाधिकृत कालोनियां नियमित होंगी और निवासियों को मालिकाना हक दिए जाऐंगे।
2. **सबके लिए सस्ते घर** : हम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घर बनाऐंगे। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के पास वर्तमान में 200 एकड़ जमीन है, जिसको सस्ते घरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. **झुग्गी झौपड़ी वालों के लिए उसी जगह घर बनाना** : झुग्गीवासियों के लिए उसी जगह प्लाट/फ्लैट बनाकर दिए जाऐंगे जहां पर झुग्गी झौपड़ियां स्थापित हैं।

सच्चाई

अनाधिकृत कालोनियां

ए– तीन साल बीत चुके है परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक भी अनाधिकृत कालोनी को पास नही किया है।

बी– आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के साथ सौतेला बर्ताव किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नही हुआ है।

सी– दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 4200 करोड़ रुपया अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए खर्च किया था और 895 अनाधिकृत कालोनियां पक्की की थी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद इन अनाधिकृत कालोनियों में विकास ठप्प हो गया है क्योंकि विकास के नाम पर इन्होंने एक ईंट भी नही लगाई है और न ही एक भी कालोनी को पक्का किया है।

सबके लिए सस्ते घर एवं झुग्गी झौपड़ी वालों के लिए उसी जगह घर बनाना

ए– आम आदमी पार्टी के 2015 के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। केजरीवाल सरकार के पास खाली जमीन उपलब्ध है इसके बावजूद भी उन्होंने गरीबों के लिए एक भी मकान नही बनाया है।

बी– यद्यपि आम आदमी पार्टी ने कागजों पर बड़े–बड़े वायदे किए और यदि केजरीवाल सरकार ने धरातल पर कुछ कार्य किया होता तो कड़कड़ाती सर्दी के कारण सैंकड़ों जान नही जाती।

सी– आम आदमी पार्टी ने झुग्गी झौपड़ी वालों को उनकी जगह पर मकान बनाने की बात कह कर गुमराह किया था। जबसे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है तब से लेकर अब तक दिल्ली सरकार ने एक भी झुग्गी की जगह मकान नही बनाए है।

डी– इसके विपरित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अजय माकन बनाम दिल्ली सरकार (W.P.(C) 11616/2015) के द्वारा शकूर बस्ती में होने वाली तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी जबकि यह तोड़फोड़ दिल्ली सरकार में पीडब्लूडी मंत्री श्री सतेन्द्र जैन के क्षेत्र में हुआ था। श्री अजय माकन ने शकूर बस्ती में बेघर हुए लोगों तथा उस क्षेत्र में रोशनी व शौचालय की सुविधाएं भी कोर्ट के आदेश पर करवाई थीं।

- **शहरी गरीब के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 93 प्रतिशत घरों का आवंटन आप पार्टी की दिल्ली सरकार नही कर पाई है** : कांग्रेस सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के द्वारा शहरों के आधुनिकीकरण की योजना चलाई गई थी तथा शहरों के गरीबों को मूलभूत सुविधा देने के लिए इस योजना के तहत दिल्ली में 55,424 घर बनाने के लिए मंजूरी मिली थी परंतु 31,424 घर ही बन पाए और केवल 2,201 घर ही आवंटित किए जा सके।
- **प्रधानमंत्री आवास योजनाः** केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह लक्ष्य था कि राज्य इस बात को लेकर सर्वे करेगा कि कितने घरों की मांग है। यह सर्वे में दिल्ली में 30 जून 2017 तक पूरा होना था परंतु अभी तक सर्वे का काम पूरा नही हुआ है।

सड़के तथा फ्लाई ओवर

ए– दिल्ली की सड़के गर्मी और वर्षा के कारण टूटी पड़ी है परंतु केजरीवाल सरकार के पास इनको ठीक करने का कोई समय नही है जबकि काफी नागरिकों को सड़कों में होने वाले गड्डों के कारण जान गंवानी पड़ी है।

बी– दिल्ली सरकार के द्वारा की जाने वाली यह लापरवाही का ही मामला नही है परंतु मुख्यमंत्री तथा पीडब्लूडी मंत्री को इन मौतों के लिए व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए।

सी– नवम्बर 2017 में पीडब्लूडी के द्वारा एक आंतरिक सर्वे करवाया गया जिसमें यह खुलासा हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर 3,793 गड्डे पाए गए जो न सिर्फ लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है बल्कि जिनके कारण सड़कों पर जाम भी लगते है।

डी– केजरीवाल सरकार के बनने के बाद उन्होंने 'redesigning the existing roads in Delhi' का नारा दिया था। सड़कों को दोबारा डिजाइन करने की बात तो दूर रही परंतु वे पहले से मौजूद सड़कों व फ्लाई ओवरों का रख रखाव भी नही कर पा रहे है।

ई– जिस समय दिल्ली सरकार कुंभकरणीय नींद में सो रही थी उस समय लाजपत नगर और अक्षरधाम के फ्लाई ओवर में 8 इंच के बड़े–बड़े गेप आ गए। सरकार ने इन फ्लाई ओवरों पर मरम्मत का कार्य तब शुरु किया जब मीडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस बात को उठाया।

एफ– केजरीवाल सरकार की एक और उपलब्धि है यह है कि जब से वह सत्ता में आई है तब से उन्होंने एक भी नया फ्लाई ओवर नही बनाया है। केजरीवाल ने बड़े–बड़े विज्ञापन देकर यह दावा किया था कि उन्होने विकास पुरी से मीरा बाग फ्लाई ओवर के बनाने में पैसे बचाए है परंतु एक आरटीआई तथा सीएजी रिपोर्ट के द्वारा यह पता लगा कि आप पार्टी सरकार के यह दावे निराधार थे और उन्होंने झूठे विज्ञापन देकर वाह–वाही लूटने की कोशिश की थी।

दिल्ली में सीवरेज व्यवस्था

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम और पीडब्लूडी को कई बार दिल्ली में मानसून आने से पहले सफाई व्यवस्था दूरस्त करने के लिए आदेश दिए थे। जब यह कार्य नही हो पाया तो उच्च न्यायालय ने अपने 26.4.2017 के आदेश से यह सुझाव दिया कि कॉओर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिसमें संबधित विभागों को रखा जाएगा ताकि सार्वजनिक सड़कों और नालों की सफाई की समस्या से निजात पाई जा सके। कॉओर्डिनेशन कमेटी खुले पड़े मेनहोल तथा सड़के जो या तो पूरी नही बनी है या जिन पर खुदाई इत्यादि हुई है। जो सामान्य जनता के लिए खतरनाक है और उन पैदल यात्रियों के लिए जब पानी ज्यादा बहता है या सड़कों पर पानी का जमाव हो जाता है।
- पीडब्लूडी विभाग की स्टेटस रिपोर्ट में झूठे दावे किए गए थे। दिल्ली विधानसभा की पेटिशन कमेटी ने जब नालों का इंस्पेक्शन किया तो पाया कि गंद व कूड़े से भरे हुए है जबकि साथ चलने वाले अधिकारियों ने स्टेट्स रिपोर्ट में यह दावा किया था सभी सड़कों की 100 प्रतिशत डिस्लिटिंग हो चुकी है। पेटीशन कमेटी ने जब सामान्य जनता से साईट की इंस्पेक्शन करते समय बातचीत की तो पता चला कि अधिकारियों द्वारा किए गए दावे ठीक नही थे।
- इन दौरों के दौरान कमेटी के सामने वो हादसा भी हुआ जिसमें पानी के ओवरफ्लो के कारण मेनहोल ढक गया था जिसके कारण एक मोटरसाईकिल सवार गिर गया था। जबकि उस दिन एक बूंद भी बारिश का पानी नही गिरा था। जबकि कमेटी के साथ चलने वाले अधिकारी यह दावा कर रहे थे कि डिस्लिटिंग की कार्यवाही 100 प्रतिशत हो चुकी है।
- पीडब्लूडी के मुख्य सचिव ने पेटीशन कमेटी को जो स्टेट्स रिपोर्ट दी थी वह झूठी और मनघंड़त साबित हुई। जिन नालियों और नालों के बारे में कहा गया था कि पीडब्लूडी ने उनकी डिस्लिटिंग कर दी है वे नाले और नालियां गाद, गंदगी से भरे हुए पाए गए जहां पर गाद ने नालियों को रोका हुआ था।
- कमेटी ने पीडब्लूडी के अन्तर्गत आने वाली नालियों व नालों के औचक निरीक्षण में यह पाया कि उनकी स्थिति पीडब्लूडी के दावों के उलट है। वे मानसून के लिए तैयार नही थे। ठेकेदारों को डिस्लिटिंग के काम के लिए पैसा दे दिया गया था परंतु ऐसी कोई प्रणाली नही थी कि जो यह पता लगा सके कि कार्य सच में हुआ है या नही। कमेटी इस स्थिति में नही थी कि वह दिल्ली के प्रत्येक नाले का निरीक्षण कर सके। परंतु उनके औचक निरीक्षण से यह पता चलता है कि विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

रेहडी पटरी

1. कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश भर के रेहड़ी पटरी वालों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD) ACT, 2014 बनाया था। इस कानून के तहत अकेली दिल्ली में 5 लाख रेहड़ी पटरीवालों को लाईसेंस दिया जाना था ताकि उनको पुलिस तथा निगमों के हाथों के द्वारा होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।
2. 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले खुद केजरीवाल रेहड़ी पटरीवालों के पास गए थे और उनसे यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर सभी रेहड़ी पटरी वालों को लाईसेंस दिए जाने की प्रक्रिया को शुरु कर देंगे।
3. सच्चाई यह है कि आज तक एक भी किसी रेहड़ी पटरी वालें को दिल्ली लाईसेंस नही दिया गया हैं क्योंकि सरकार लाईसेंस देने की प्रक्रिया को लेकर नियम नही बना पाई है।

4. जहां एक ओर केजरीवाल सरकार सोती रही, दूसरी ओर लाखों रेहड़ी पटरीवालों को पुलिस डीयूएसआईबी तथा निगमों ने गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया। जो बचे हुए है वे बहुत भारी रिश्वत देकर काम कर रहे है क्योंकि उनको 2014 के कानून के हिसाब से अभी लाईसेंस नही दिया गया है। इंस्पेक्टर राज के चलते गरीब रेहड़ी पटरी वाले रिश्वत देकर अपना काम चला रहे है।
5. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाकर रेहड़ी पटरी वालों को लाईसेंस देने की प्रक्रिया को तेजी से करने की मांग की तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में दिल्ली सरकार के सचिव को तलब किया ताकि वह यह बता सके कि लाईसेंस देने की प्रक्रिया किन कारणों से हुई है।
6. आप पार्टी की दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता के कारण न सिर्फ दिल्ली के 5 लाख रेहड़ी पटरीवालों को परेशानियां झेलनी पड़ी है परंतु उन पर निर्भर उनके घरवालों को भी समस्याएं आई है। यदि हम प्रत्येक घर में 4 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो इस प्रकार पूरी दिल्ली में 20 लाख लोग प्रभावित हुए है।

विधायक फंड के अन्तर्गत आने वाले विकास कार्यों की धीमी गतिः

- दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय में विधायक फंड शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत आता था और वह विभाग इस फंड के लिए नोडल एजेंसी भी था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने डूडा (Delhi Urban Development Authority) को विधायक फंड के लिए नोडल एजेंसी बना दिया। आप पार्टी के गैर जिम्मेदाराना निर्णय के कारण पहले ढ़ाई वर्षों में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे परंतु उनमें से ज्यादातर पूरे नही हुए। फंड का बहुत सारा पैसा बिना इस्तेमाल किए रह गया।
- वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 1704 कार्यों को मंजूरी मिली परंतु केवल 787 जो कि 50 प्रतिशत ही थे शुरु हो सके। केवल 31 प्रतिशत प्रोजेक्ट उस वर्ष में पूरे हो पाए।
- 2017–18 की पहली तिमाही में MLA-LAD प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोई प्रोग्रेस नही हुई। ढ़ाई साल के बाद अरविन्द केजरीवाल ने अपनी गलती को महसूस किया और सारे काम दोबारा शहरी विकास के पास स्थानांतरित कर दिए। परंतु केजरीवाल के अपरिपक्व निर्णय के कारण दिल्ली को भुगतना पड़ा।
- 2017–18 के दौरान लिए गए प्रोजेक्ट समय पर पूरे नही हो सके क्योंकि 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है।
- इस प्रकार उपर दिए गए तथ्यों से यह निर्णय निकलता है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार के अन्तर्गत विकास के मामले में बहुत पिछड़ गई है।
- **गरीबों के लिए नाईट शैल्टर बढ़ाने की जगह आम आदमी पार्टी ने इनको कम कर दिया** :
  कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी के 3 वर्षों के कार्यकाल 2011–14 के बीच में 120 नाईट शैल्टर जोड़े थे जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने उल्टे 2 नाईट शैल्टर कम कर दिए। हैरानी की बात यह है कि जिस समय केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को शपथ ली थी उस समय 263 नाईट शैल्टर कार्य कर रहे थे परंतु अब वे कम होकर 261 रह गए है।

- **Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT) योजना के तहत आने वाले प्रोजेक्ट में कोई उन्नति नहीः** AMRUT योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट सेंशन हुए थे जिसमें से 4

प्रोजेक्ट सीवर नेटवर्क, 6 प्रोजेक्ट पानी की लाईने बिछाकर घरों के लिए पानी का नेटवर्क बढ़ाना, तथा एक प्रोजेक्ट सीवेज ट्रीटमेंट केपेसिटी को बढ़ाने के लिए था। इन प्रोजेक्ट के लिए 97.75 करोड़ रुपया दे दिया गया है परंतु अभी तक कोई प्रगति नही हुई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बढ़ाने के लिए अभी तक कोई कंसलटेन्ट भी नियुक्त नही हुआ है।

- **National Urban Livelihood Mission**:
- हाउसिंग एंड अरबन पावर्टी एलीविएशन मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से चलने वाली पूरानी योजना को बदल दिया है।
- योजना को अभी शुरु होना है क्योंकि दिल्ली के राजस्व विभाग के द्वारा आय प्रमाण पत्र बनाने में समस्याएं आ रही है।
- दिल्ली सरकार को यह योजना राजस्व विभाग के द्वारा लागू होनी है परंतु इसका बजट शहरी विकास विभाग के पास है।
- इस योजना के तहत नाईट शैल्टर को चलाने व रख रखाव के लिए फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु दिल्ली सरकार की सुस्ती के कारण बहुत सारा पैसा अभी बिना इस्तेमाल किए बचा हुआ है।

#महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की विफलताएं

आम आदमी पार्टी सरकार महिला विरोधी

- तीन वर्ष के पश्चात भी दिल्ली के मंत्रीमंडल में एक भी महिला नही।
- आप पार्टी बहुत सारे विधायकों तथा वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा बलात्कार के मामले सामने आए परंतु केजरीवाल ने नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की।
- आप पार्टी की दिल्ली सरकार के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री को सेक्स स्कैंडल के चलते अपना पद गंवाना पड़ा परंतु अभी तक इस मंत्रालय के लिए कोई मंत्री नही बनाया है। उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया अन्य मंत्रालयों के साथ इस मंत्रालय को भी देख रहे है।
- पंजाब चुनाव के दौरान पंजाब चुनाव के दौरान आप पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें की थी, परंतु उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई।

लिंग संसाधन केन्द्र (Gender Resource Centre) बंद हो गए।

- जेन्डर रिसोर्स सेन्टर कांग्रेस की दिल्ली सरकार का फ्लेगशिप कार्यक्रम था जिसके द्वारा गरीब तबके की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना था।
- इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, कानूनी अधिकार, आर्थिक मजबूती जिसमें स्कील बिल्डिंग, छोटे–छोटे काम धंधे, उद्यमी विकास, स्वास्थ्य तथा साक्षरता को बढ़ाना इत्यादि थे।
- इन केन्द्रो को उपर लिखित गतिविधियों के अलावा भी सामाजिक पहल के कार्यक्रम जैसे आधार कार्ड, अन्नश्री कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री जन–धन योजना को सामान्य जनों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी उपयोग किया गया था। इस प्रकार इन केन्द्रों ने न सिर्फ गरीब महिलाओं की भलाई के लिए कार्य किए बल्कि समाज के गरीब तबके के सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने का भी कार्य किया।
- इन केन्द्रों को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, महिला एवं बच्चों के लिए कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं, कानूनी एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वोकेशनल तथा शिक्षाविदों की सहायता से चलाया जा रहा था।
- इन केन्द्रों को दिल्ली सरकार ने एक आदेश के द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से 31 मई 2016 को बंद कर दिया। जिसके कारण तकरीबन 103 जीआरसी केन्द्र, 26 एक्सटेन्शन केन्द्र, 5 होमलेस रिर्सोस सेन्टर, जिला रिसोर्स सेन्टर तथा 43 आवाज उठाओं केन्द्र बंद हो गए।
    - एक झटके में ही हजारों लोग बेरोजगार कर दिए गए तथा लाखों लाभार्थियों तथा विद्यार्थी जिनका वोकेशलन कोर्स में पंजीकरण हुआ था, उनको काफी परेशानियां हुई।
    - आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने जान बूझकर इन केन्द्रों को बंद किया था। कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नही दिए गए थे। यही हाल महिलाओं के लिए चलाई गई 181 हैल्प लाईन का हुआ जो कि स्टाफ को वेतन न दिए जाने के कारण बंद कर दी गई।

महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार असंवेदनशीलता

- दिल्ली सरकार 'निर्भया फंड' को इस्तेमाल करने में विफल रही है और इस फंड से वन स्टोप सेन्टर बनाने के लिए पैसा नही ले सकी। जबकि इस सेन्टर के द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, उनको कानूनी सहायता तथा पीड़ितों को अस्थाई शरण देने का प्रावधान किया जाना था।
- 2016–17 में घरेलू हिंसा के 6100 मामले दर्ज हुए थे जिसमें से केवल 224 महिलाओं को कानूनी सहायता मिल सकी और 18 महिलाओं को दिल्ली सरकार ने वित्तिय सहायता प्रदान की।
- 3 वर्ष बीत चुके है, बसों में मार्शल का कोई अता पता नही है जबकि आम आदमी पार्टी का यह बड़ा चुनावी वायदा था।
- आप पार्टी ने निर्भया फंड से डीटीसी तथा कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वायदा किया था। महिला एवं बाल विकास के केन्द्रीय मंत्रालय को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नही भेजा है।
- जो थोड़े बहुत सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है उनकी देखभाल के लिए कोई प्रणाली नही है।
- 3 वर्ष बीतने के बाद भी लास्ट माईल कनेक्टीविटी में सुधार करने के लिए कोई योजना नही बनाई गई है। जबकि इस योजना के द्वारा महिला सुरक्षा को मजबूत किया जाना था।
- आप पार्टी ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाने का वायदा किया था परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले से चल रहे 77 प्रतिशत हॉस्टल बंद कर दिए गए। 2013–14 में महिलाओं के लिए 18 हॉस्टल थे जिसमें से 3 वर्षों में 14 बंद कर दिए गए और 2016–17 में केवल 4 हॉस्टल चल रहे है।

महिलाओं का स्वास्थ्य जोखिम में

- 2014–15 तथा 2016–17 के बीच में गर्भवती महिलाओं की कॉसलिंग के मामलों में 26 प्रतिशत की कमी आई है क्योंकि यह 1,68,808 से कम होकर 1,24,759 रह गई।
- इस अवधि के दौरान स्तनपान कराने वाली महिलाओं की कॉसिलिंग में 20 प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि यह 1,28,554 से कम होकर 1,02,383 रह गई है।
- मातृ मृत्युदर के मामले 21 प्रतिशत बढ़े है, 2014–15 में जहां ये मामले 399 थे वे 2016–17 में बढ़कर 508 हो गए।

सुरक्षित व साफ सार्वजनिक शौचालय एक सपना बनकर रह गए।

स्वच्छ भारत मिशन (दिल्ली सरकार के विभाग डीयूएसआईबी के अन्तर्गत काम करता है)

- 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान डीयूएसआईबी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली सरकार के अन्तर्गत एक भी प्रोजेक्ट पूरा नही किया है।
- डीयूएसआईबी ने 2017–18 तक 1314 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा था परंतु सितम्बर 2017 तक केवल 384 शौचालय बने अर्थात लक्ष्य का केवल 29 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका।
- स्वच्छ भारत मिशन के शुरु होने अर्थात 2 अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2017 तक डीयूएसआईबी ने केवल 384 शौचालय बनाए है।

एक्शन एड इंडिया ने दिसम्बर 2016 में शौचालयों का एक सर्वे किया था जिसमें निम्न तथ्य उजागर हुए:

- 3 में से 1 शौचालयों में भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय का प्रावधान नही है।
- 71 प्रतिशत शौचालयों में प्रतिदिन सफाई नही होती।
- 72 प्रतिशत शौचालयों पर आसानी से दिखने वाले साईन बोर्ड नही है।
- 65 प्रतिशत शौचालयों में फ्लश की सुविधा नही है।
- 50 प्रतिशत शौचालयों में पानी की सुविधा नही है।
- 28 प्रतिशत शौचालयों में दरवाजें नही है।
- 45 प्रतिशत शौचालयों में अंदर से बंद करने की सुविधा नही है।
- 50 प्रतिशत से अधिक शौचालयों में रोशनी की सुविधा नही है।
- 64 प्रतिशत शौचालयों में कोई सुरक्षा कर्मी नही है जो कि एक चिंता का विषय है।

लाडली योजना के बजट में कटौती

- इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए वित्तिय सहायता की जाती है।
- लाडली योजना के लिए जो बजट 112.29 करोड़ था वह 2016–17 में कम करके 96.68 करोड़ कर दिया।

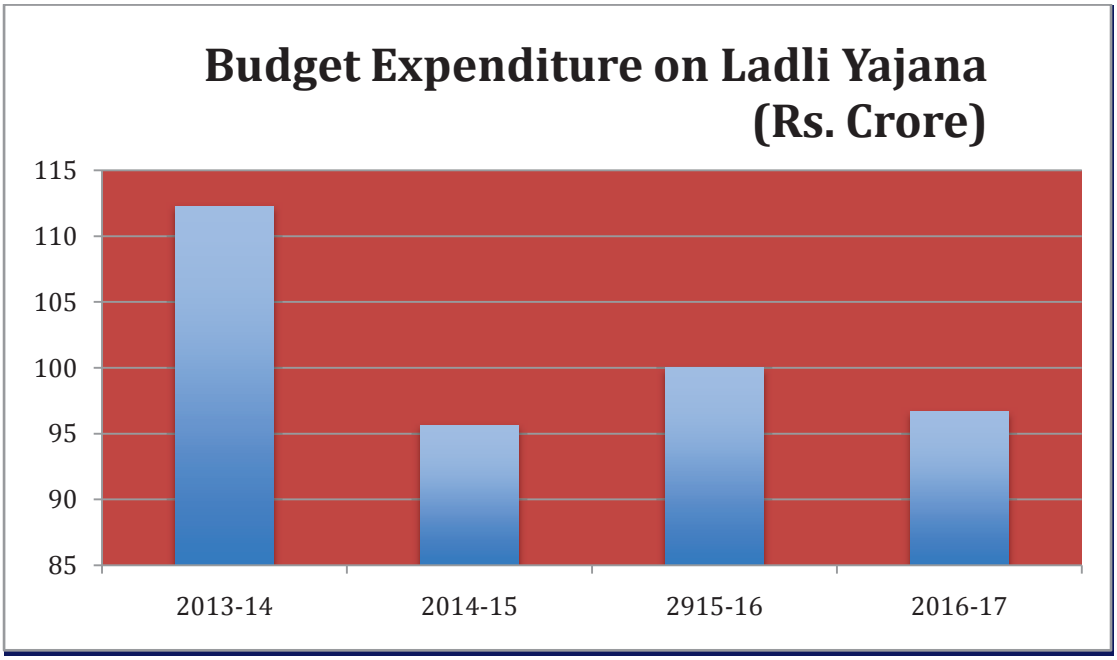

#पर्यावरण के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विफलाएं

- दिल्ली भारत के उन पॉच प्रदूषित राज्यों राज्यों में सम्मलित है जो विश्व के 15 प्रदूषित राज्यों में आते है जहां पर प्रदूषण का लेवल PM2.5. दिल्ली में हाल ही में एक ऐसा प्रदूषण का इतना उच्च स्तर था जिसके लिए स्थानीय व अन्य कारक जिम्मेदार थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की ढुलमुल रवैये के कारण भविष्य में ऐसी स्थिति न बने इसकी भी काई गांरटी नही है।
- AQI . स्टेन्डर्ड के हिसाब से दिल्ली को PM 10 का स्तर 74 प्रतिशत, PM2-5 का स्तर 70 प्रतिशत तथा नाईट्रोजन डायोक्साईड के स्तर को 37.5 प्रतिशत कम करना पड़ेगा। परंतु वर्तमान की दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से भविष्य में ऐसा होने वाला नही है।

बसों की कमी : आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में डीटीसी के बेड़े से 1273 बसे हटा दी गई। 2013–14 यानि कांग्रेस कार्यकाल में डीटीसी के बेड़े में 5223 बसें थी जो कि अगस्त 2017 में कम होकर 3,951 रह गई। डीटीसी के बेड़े के इस्तेमाल में कमी आई है, जहां 2013–14 में यह इस्तेमाल 85.51 प्रतिशत था वह 2015–16 में घटर 83.63 प्रतिशत रह गया। जिस शहर में पहले से ही डीटीसी बस के बेड़े का आकार कम हो रहा है उसमें डीटीसी के बेड़े के उपयोग में कमी सरकार की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कांग्रेस के आखिरी 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली में डीटीसी की 3,125 बसें जोड़ी गई थी। जबकि केजरीवाल सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में केवल 2 बसे डीटीसी के बेड़े में जोड़ी है। डीटीसी के बेड़े में घटती बसों के कारण लोगों को अपने प्राईवेट वाहन चलाने पड़ रहे है जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है।

- **मेट्रो किराए में बढ़ौतरी :** केजरीवाल सरकार ने लास्ट माईल कनैक्टीविटी को बढ़ाने की बजाए एक साल में दो बार मेट्रो के किराए बढ़ा दिए तथा कम से कम 8 से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 60 रुपये किराया कर दिया गया जिसके कारण आम जनमानस को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली में 2004 व 2009 में दो बार मेट्रो के किराए बढ़ाए गए थे। मेट्रो किराए बढ़ने के कारण मेट्रो से चलने वाले यात्री जून 2016 में 25.7 लाख रह गए जबकि मई में इन यात्रियों की संख्या 26.5 लाख थी अर्थात 0.8 लाख यात्रियों की कमी आई। और यह कमी अक्टूबर में 24.2 लाख रह गई जबकि सितम्बर में यह संख्या 27.4 लाख थी। क्योंकि सितम्बर में दोबारा किराए बढ़ाए गए थे। अक्टूबर में 11 प्रतिशत यात्रियों की कमी यह दर्शाती है कि यात्रियों यात्रा के लिए दूसरे वाहनों का इस्तेमाल शुरु कर दिया है जिसके कारण अक्टूबर–नवम्बर 2017 में प्रदूषण का स्तर उच्च स्तर पर रहा।

- **मेट्रो फेस–4 प्रोजेक्ट एक साल से लटका हुआ है :** दिल्ली शहर का महत्वकांक्षी फेस–4 प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार के वित्तिय कारणों की वजह से 1 वर्ष लटका हुआ है यदि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो न सिर्फ दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि 20 लाख वाहन सड़कों से हट जाऐंगे तथा 19 लाख टन वार्षिक प्रदूषक कम होंगे। डीपीआर एप्रूवल के लिए फाईल 2014–15 में जमा हो गई थी जबकि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में घूम रही हैं। अगस्त 2017 में नई मेट्रो पॉलिसी आ चुकी है और ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार नई पॉलिसी की शर्ते पूरी करने में कामयाब होगी।

- **दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर** : दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रोक रखा है क्योंकि दिल्ली सरकार और नेशनल केपिटल रीज़न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के बीच में फ्रेश फंडिंग पेटर्न का मामला है क्योंकि उसको आर.आर.टी. एस के द्वारा लागू किया जाना है। यह छोटा से मुद्दा है परंतु सरकार ने जानबूझ कर इस फाईल का दबा रखा है।

  36 प्रतिशत यात्री दिल्ली और मेरठ के बीच में चलते है जो कि कार का इस्तेमाल करते है, 32 प्रतिशत यात्री सब–अरबन रेलवे तथा 27 प्रतिशत अपने दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते है। यदि दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो कारों के इस्तेमाल में 22 प्रतिशत, दुपहिया वाहनों में 15 प्रतिशत की कमी आ जाएगा और 46 प्रतिशत के करीब यातायात दिल्ली मेरठ हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिफ्ट हो जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से 7 लाख यात्री इससे यात्रा करेंगे। जिसके कारण प्रदूषण में कमी आएगी।

प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (PUC) की असफलता

- दिल्ली में 971 प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र है परंतु परिवहन विभाग के पास केवल 28 इंस्पेक्टर हैं परंतु एक ही इंस्पेक्टर, जो जमीनी स्तर पर इतने सारे केन्द्रों की जांच करने लिए उपलब्ध है।
- एक तरफ तो अरविन्द केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का दावा करते है परंतु प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र में भ्रष्टाचार के कारण वाहनों का प्रदूषण बढ़ा है जिसमें नकली सोफ्टवेयर के द्वारा झूठे पास बनाए जाते है तथा गलत टेस्टों को भी पास किया जाता है। ईपीसीए के विश्लेषण के अनुसार 13.7 लाख के एमीश्न आंकड़ों में से 20 प्रतिशत टेस्ट में प्रदूषकों की 0 वैल्यू मिली है, जो कि इस कार्यक्रम की कार्यकुशलता और सरकार के लाईसेंसिग प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- **कार्यक्रम की कमजोर अनुपालनाः** 1 नवम्बर 2016 से 31 जनवरी 2017 के बीच के उपलब्ध आंकड़ो पर आधारित ईपीसीए की रिपोर्ट यह बताती है कि 23 प्रतिशत वाहन ही सिर्फ टेस्ट के लिए आए। जो सरकार की नाकामी को बताता है, जबकि 100 प्रतिशत वाहनों का टेस्ट होना चाहिए।
- **फेल होने की दर बहुत कम – तकरीबन सभी वाहन पास :** जो वाहन टेस्ट के लिए आते है उनमें फेल होने की दर बहुत कम है। केवल 1.68 प्रतिशत डीजल के वाहन स्मोक डेन्सिटी टेस्ट पर फेल हुए हैं और 4.5 प्रतिशत पेट्रोल के वाहन CO तथा HC टेस्ट पर

फेल हुए है। इस प्रकार यह कार्यक्रम इतना सक्षम भी नही है कि 15 से 20 प्रतिशत उन वाहनों को पकड़ पाए जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते है।

- **पर्यावरण कर (Environment Tax) को खर्च न कर पाना** : दिल्ली में परिवहन व्यवस्था जर्जर हालत में है परंतु सरकार ने Environment Tax के तहत 829 करोड़ रुपया माल ढ़ोने वाले वाहनों से एकत्रित किया जिसमें से केवल 93 करोड़ रुपया ही खर्च किया जा सका। यह राशि 6 नवम्बर 2015 से 1 नवम्बर 2017 के बीच एकत्रित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसके तहत एकत्रित की जाने वाली राशि को सड़कों, सार्वजनिक परिवहन तथा साईकिल ट्रेक बनाने के लिए खर्च किया जाना था।

अब हम समस्याओं को जानते हैं, यहां पर हम कुछ समाधान देना चाहते हैं जो कि दिल्ली कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस ने प्रस्तावित किए है :

- बसों की संख्या में वृद्धि करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना
- मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाएं और किराए में कमी करें
- ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकें
- डीजल का इस्तेमाल खत्म करना और इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहित करना
- **फसल अवशेष जलाना बंद करो**– हम केंद्र सरकार से किसानों की जरूरत के हिसाब से सब्सिडी देने के लिए आग्रह करते हैं ताकि हमें सांस ले सकें।
- सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करें और उस पर सब्सिडी भी दें।
- तत्काल आधार पर सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग हो ।
- कचरा जलाने पर तत्काल रोक लगे।
- इकट्ठा किया गया पर्यावरण सैस को खर्च किए जाने की शुरुआत की जानी चाहिए।
- ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने शुरु करें।

पेड़ों का काटना – उपरोक्त समस्याओं के अलावा, "Tree Blindness & Tree Cutting" की समस्या है, जो बढ़ रही है। पर्यावरणविदों का दावा है कि वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते है परंतु वे खर्च नही होते। लेकिन नई दिल्ली नेचर सोसाइटी के संस्थापक पर्यावरण मंत्री वेरहैन खन्ना ने कहा– आज जीवित रहने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक हैं, पर्यावरण हम सबको प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जो हम इसमें सुधार के लिए जो कर सकते है उसके लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि हमारी भविष्य की पीढ़ियों का अस्तित्व इस पर निर्भर है

कांग्रेस सरकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय

- **सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्वच्छ हवा मिल सके।**
- **वृक्षारोपण के द्वारा दिल्ली को हरा भरा किया जाए**

मुफ्त पानी की सप्लाई का झूठ

The Indian EXPRESS

Hardlook: My father had died and my mind was occupied with storing water, says Sangam Vihar resident

Residents say the timing of the arrival of the tankers is not certain and this forces them to be on alert.

30 SHARES SHARE

- केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही जल सब्सिडी का फायदा केवल 8: दिल्ली वासियों को हुआ है जिसका परिणाम यह है कि बाकी दिल्ली वासियों को पिछले दो वर्षों में पानी एवम सीवरेज बिल 3 गुणा अधिक देना पड़ा।
- दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनी में 95 प्रतिशत जल सप्लाई का पानी डब्लू.एच.ओ. द्वारा स्थापित मानकों पर खरा नहीं है।
- नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कमान क्षेत्र में आने वाले 88,000 घरों में कोई भी सरकारी जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर जल आपूर्ति की प्रक्रिया में तकरीबन 48 प्रतिशत जल की क्षति होती हैं लेकिन दिल्ली में रिसाव, चोरी एवम अन्य कारणों से यह क्षति 62 प्रतिशत तक हैं।
- मालवीय नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 7,200 घरों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ मात्र 4 टैंकर उपलब्ध हैं। (कुछ आवास– 45,000)
- दिल्ली में कुल कच्ची कॉलोनी की संख्या 1522 हैं। (कुल योग्य कॉलोनी= 1665–109–34=1522) जिसमें से मात्र 263 कॉलोनियों में ही सीवरेज सुविधा उपलब्ध हैं। अर्थात कुल कच्ची कॉलोनियों में से केवल 17.3 प्रतिशत में ही यह सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

पानी को लेकर किए गए वादे व उनकी सच्चाई

- **वायदा :** आम आदमी पार्टी यह वादा करती हैं कि हर घर को दिल्ली जल बोर्ड मीटर कनेक्शन के साथ 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराएगी ।
- **दावा :** केजरीवाल सरकार का यह दावा है कि दिल्ली की 87 प्रतिशत आबादी को निशुल्क पानी की योजना का लाभ हुआ है।
- वास्तविकताः केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही जल सब्सिडी का फायदा केवल 8 प्रतिशत दिल्ली वासियों को हुआ है जिसका परिणाम यह है कि बाकी दिल्ली वासियों को पिछले दो वर्षों में पानी एवम सीवरेज बिल 3 गुणा अधिक देना पड़ा।
- **गणना** : 20,000 लीटर निशुल्क पानी की योजना का लाभ केवल 4.28 लाख घरों को हुआ है जो कि दिल्ली के लगभग 46 लाख घरों का 8 प्रतिशत से भी कम हैं।
- **आप का वायदा** : दिल्ली जल बोर्ड एक्ट में संशोधन करके स्वच्छ पानी को जनता का अधिकार बनाया जायेगा।
- **वास्तविकताः** अभी तक ऐसा कोई भी संशोधन विधान सभा में पारित नहीं हुआ है। स्वच्छ पानी को जनता का अधिकार बनाने की बजाए प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति में भी कमी आ गई हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति, प्रति दिन 48–50 गैलन पानी उपलब्ध होता था जबकि वर्ष 2016–17 में यह घटकर 47 गैलन प्रति दिन हो गया है।

PRADESH CONGRESS COMMITTEE
DELHI